दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश से एक साथ प्रकाशित ››› दिल्ली ››› गाजियाबाद ››› नोएडा ››› ग्रेटर नोएडा ››› हापुड़ ››› अमरोहा ››› बागपत ››› मेरठ ››› मुजफ्फर नगर ››› बिजनौर ››› मुरादाबाद ››› बुलंदशहर ››› अलीगढ़ ››› फरीदाबाद ››› गुड़गांव ››› सोनीपत

RNI-UPHIN/2009/30721

शुक्रवार 25 जुलाई 2025
सूर्योदय प्रात: 05:38 बजे
सूर्यास्त सांय 19:18 बजे

एनसीआर टुडे

करंट न्यूज करंट व्यूज

पृष्ठ 4 दुनिया की लाखों जिन्दगियां में जहर घोलता अकेलापन

उत्तर प्रदेश और दिल्ली से एक साथ प्रकाशित | वर्ष: 16 | अंक : 280 | गाजियाबाद, शुक्रवार 25 जुलाई 2025 | मूल्य : ₹ 2 | पेज : 06 | विक्रमी संवत् 2081 | युगाब्द 5126 | शाक 1946

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 दोषियों को बरी करने के फैसले पर लगाई रोक

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में दोषी सभी 12 लोगों को बरी करने के बम्बई उच्च न्यायालय के 21 जुलाई के फैसले पर गुरुवार को रोक लगाते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित किया। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय के फैसले को अन्य लंबित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) मामलों में मिसाल नहीं माना जाएगा।

शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर संबंधित सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया। पीठ ने इस दलील पर गौर किया और स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा। उच्च न्यायालय ने सोमवार 21 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया था।

उसने विशेष मकोका अदालत के वर्ष 2015 के फैसले को पलटने हुए उसके उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें पांच आरोपियों को मौत की सजा और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मकोका अदालत ने कमाल अंसारी (अब मृत), मोहम्मद फैसल शेख, एहते-शाम सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान और आसिफ खान को मौत की सजा सुनाई थी। अदालत ने तनवीर अहमद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख मोहम्मद, मोहम्मद साजिद मरगूब अंसारी, मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, सुहैल महमूद शेख और ज़मीर अहमद शेख को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

अनिल अंबानी की 50 कंपनियों पर ईडी की रेड!

● 3000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का है यह मामला ● यस बैंक से लिए पैसों का गलत इस्तेमाल का आरोप

मुंबई (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें करीब 50 कंपनियों शामिल है। 25 से ज्यादा लोगों से भी पूछताछ की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यस बैंक से लिए 3000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में गुरुवार, 24 जुलाई को की गई ये रेड दिल्ली और मुंबई में चल रही है। ये छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत की जा रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ये कार्रवाई सीबीआई की ओर से दर्ज दो एफआईआर और सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई है।

बिहार विधानसभा में संग्राम एसआईआर जमकर हंगामा

● डिप्टी सीएम सम्राट और तेजस्वी के बीच तू-तू, मैं-मैं की नौबत

पटना (एजेंसी)। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में दूसरे सेशन के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। तेजस्वी ने सदन में कहा, वोटर वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा हो रहा है। बीएलओ खुद साइन कर रहे हैं।

पत्रकार पर एफआईआर कराने वाले आप कौन होते हैं। इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भड़क गए और कहा, आप कौन होते हैं। जिसका बाप अपराधी है, वो क्या बोलेगा। चल हट..लुटेरा हो-लुटेरा...वो क्या बोलेगा। सम्राट चौधरी के बयान पर लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि, किसी के पिता को गाली देना कितना सही है।

अगर कोई घर परिवार तक आएगा तो इंसान क्या करेगा। मैं तो सदन में नहीं था, वरना मैं उनका बुखार छुड़ा देता। वो लोग गुंडा पार्टी से आते हैं। इससे पहले सदन में पेपर लीक पर तेजस्वी और डिप्टी सीएम आमने-सामने हुए। तेजस्वी ने कहा, बिहार पेपर लीक में नंबर वन है। इस पर सम्राट चौधरी ने आपत्ति जताई।

कृपया ध्यान दें! अब हर पांच साल में कराना होगा जरूरी,वरना नहीं मिलेगा लाभ

केवायसी नहीं कराई तो बंद हो जाएगा आपका राशनकार्ड

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

सरकार ने बुधवार को मौजूदा पीडीएस नियमों में संशोधन करते हुए सभी राशन कार्ड धारकों के लिए हर पांच साल में इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर यानी ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को रोकना, डुप्लिकेट कार्ड्स को हटाना और सब्सिडी को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और

सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 के तहत पीडीएस में पारदर्शिता बढ़ाने, डुप्लिकेशन को रोकने और सब्सिडी के टारगेट को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके तहत, राज्य सरकारों को सभी पात्र परिवारों के लिए हर पांच साल में ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। इस प्रक्रिया में अयोग्य परिवारों को लाभार्थी सूची से हटाया जाएगा और नवीन पात्र परिवारों को शामिल किया जाएगा। नए नियमों के अनुसार, अलग राशन कार्ड के लिए न्यूनतम आयु अब 18 वर्ष निर्धारित की गई है। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि केवल पात्र व्यक्ति ही राशन कार्ड के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त करें।

भारत और यूके के बीच हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

● पीएम मोदी बोले-कई साल की मेहनत के बाद हुआ है समझौता

लंदन (एजेंसी)। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता पर आखिरकार हस्ताक्षर हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब दोनों देशों के बीच चीजों का लेन-देन और व्यापार पहले से आसान और सस्ता हो जाएगा। फ्री ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। इस डील से न सिर्फ सामान सस्ते होंगे, नौकरियां बढ़ेंगी और दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इस डील के बाद भारतीय बाजार में यूके से आने वाले सामान सस्ते होंगे, जबकि भारत से होने वाले निर्यात में बड़ी छलांग लगने की उम्मीद है। दोनों देशों के कारोबारियों और विशेषज्ञों ने इस समझौते का स्वागत किया है। अधिकारियों ने कहा कि एफटीए के लागू होने पर 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में शुल्क नहीं लगेगा।

भारत के लिए गेमचेंजर होगी यह डील

भारत के लिए यह डील कई मायनों में गेमचेंजर मानी जा रही है। समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को 99 फीसदी उत्पादों पर ब्रिटेन में ड्यूटी-फ्री एंट्री मिलेगी। इससे लगभग 23 अरब डॉलर के व्यापार अवसर खुलने का अनुमान है। सरकार के मुताबिक, इससे भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे कपड़ा, चमड़ा, जूते, गहने, खिलौने और समुद्री उत्पादों में काम करने वाले कारीगरों, बुनकरों और दैनिक मजदूरों को सीधा फायदा होगा। लघु सेक्टर की लाखों इकाइयों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस समझौते से 95 फीसदी कृषि उत्पाद अब बिना किसी शुल्क के ब्रिटेन में निर्यात किए जा सकेंगे। वहीं, मछुआरों को 99 फीसदी समुद्री उत्पादों पर शून्य शुल्क मिलने से उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। एफटीए के जरिए महिलाएं वैश्विक वैल्यू चेन से बेहतर ढंग से जुड़ सकेंगी और उन्हें फाइनेंस तक आसान पहुंच मिलेगी। भारत के स्टार्टअप्स को ब्रिटेन के इनोवेशन हब, निवेशकों और उपभोक्ताओं तक पहुंच का बड़ा अवसर मिलेगा। भारतीय आईटी पेशेवरों, एजुकेशन एक्सपर्ट्स और सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए यूके का हाई-वैल्यू मार्केट अब और अधिक सुलभ होगा।

धोखाधड़ी के 100 फीसदी सबूत, बचकर नहीं निकल पाओगे

● राहुल गांधी के निशाने पर फिर चुनाव आयोग, बोला बड़ा हमला

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी के पास कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा 'धोखाधड़ी की अनुमति' देने के 100 प्रतिशत सबूत हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आयोग यह सोचता है कि वह इससे बच निकलेगा, तो यह उसकी 'गलतफहमी' है।

संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हमारे पास कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा धोखाधड़ी की अनुमति देने के 100 प्रतिशत ठोस सबूत हैं। 90 नहीं, पूरे 100 प्रतिशत। उन्होंने बताया कि पार्टी ने सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र की समीक्षा की है, और उसमें हजारों संदिग्ध वोटर मिले हैं जिनकी उम्र 50, 60 या 65 वर्ष है, लेकिन वे नए मतदाता के तौर पर दर्ज हैं।

राहुल गांधी ने दावा किया कि ऐसा सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि संभवतः हर निर्वाचन क्षेत्र में यह नाटक चल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जब ये सबूत सामने लाने का निर्णय लिया है, तो वह पूरी तैयारी के साथ सामने आएगी। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा,यह बहुत ही गंभीर मामला है। चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग की तरह काम नहीं कर रहा है। आज उन्होंने जो बयान दिया, वह पूरी तरह बकवास है। सच यह है कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने दो टूक कहा, अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे, तो आप गलतफहमी में हैं।

भारतीय कंपनी ने अमेरिकी धमकियों को दिखाया ठेंगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिकी प्रतिबंधों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए भारत की एक कंपनी ने दिसंबर 2024 में रूस को एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोटक रसायन एचएमएक्स भेजा। इसे ऑक्टोजेन भी कहा जाता है। विस्फोटक की कुल कीमत 1.4 मिलियन (लगभग 11.7 करोड़ रुपये) थी। यह जानकारी भारतीय सीमा शुल्क डेटा से सामने आई है। एचएमएक्स एक बेहद शक्तिशाली विस्फोटक है जिसका व्यापक इस्तेमाल सैन्य मिसाइलों, रॉकेट मोटरों, टॉरपीडो और युद्धक सामग्री में होता है। रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सौदे को लेकर अमेरिका ने गहरी चिंता जताई है। अमेरिकी सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि एचएमएक्स जैसे पदार्थ रूस के युद्ध प्रयास के लिए अहम हैं और जो भी कंपनियां या वित्तीय संस्थाएं रूस को ऐसे पदार्थ उपलब्ध कराएंगी,उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

● रूस को भेज दिया खतरनाक एचएमएक्स विस्फोटक

रूसी कंपनी प्रोम्सिन्टेज ने इस एचएमएक्स की सबसे बड़ी खेप खरीदी। इस कंपनी को यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी ने रूस की सेना से जुड़ा हुआ बताया है। अप्रैल 2025 में यूक्रेन ने इसी कंपनी की एक फैक्ट्री पर ड्रोन हमला किया था। तेलंगाना की कंपनी ने दो बार एचएमएक्स रूस को भेजा।

धर्मांतरण केस में बढ़ रहीं छांगुर बाबा की मुश्किलें

एटीएस और ईडी की जांच में चौंकाने वाला खुलासा

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यूपी एटीएस और ईडी की जांच में लगातार बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच मिल रही जानकारी के मुताबिक, छांगुर बाबा ने विदेश से मिले फंड से प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी है। यही नहीं, इन जमीनों पर प्लॉटिंग और निर्माण कार्य भी कराया गया, जिनके जरिए मतांतरण की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। प्रदेश के 300 से ज्यादा रजिस्ट्री कार्यालयों में छांगुर और उसके सहयोगियों के नाम से दर्ज रजिस्ट्री दस्तावेजों की पड़ताल शुरू हो गई है। इन सभी लोगों की सूची बनाकर सभी उपनिबंधकों को भेज दी गई है और उनके नाम पर दर्ज बैनामों का विवरण मांगा गया है। इसमें छांगुर बाबा के साथ सबरोज, शहाबुद्दीन, महबूब, नीतू उर्फ नसरीन, नवीन, बाबू, राजेश उपाध्याय और संगीता देवी के नाम शामिल है। जांच में यह भी सामने आया है कि छांगुर बाबा ने जमीन खरीद के लिए एक संगठित नेटवर्क तैयार किया था। इस नेटवर्क के जरिए प्रमुख जिलों खासतौर पर देवीपाटन मंडल को केंद्र बनाकर जमीनें खरीदी गई थीं।

बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस का कर्नाटक दांव

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक में कंठराज आयोग द्वारा 2015 में किए गए सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण (जाति जनगणना) को रद्द करने के एक महीने से भी कुछ ज्यादा समय बाद वहां की कांग्रेस सरकार ने दशहरा की छुट्टियों के दौरान 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 15 दिनों के लिए एक नया सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण यानी कास्ट सर्वे कराने का फैसला किया है। बड़ी बात ये है कि ये सर्वे ऐसे वक्त में प्लान्ड किए गए हैं, जब बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होंगी और सियासत अपने चरम पर होगा।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस बावत बुधवार (23 जुलाई) को एक टॉप लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने मधुसूदन आर. नाइक की अध्यक्षता वाले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अक्टूबर के अंत तक जाति सर्वे का रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। बैठक में सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य में हरेक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का व्यापक सर्वेक्षण होना चाहिए, चाहे उसके पास जमीन हो या न हो, इत्यादि। उन्होंने कहा कि यही सर्वेक्षण रिपोर्ट अगले बजट का आधार होगी।

पिछले कंठराज आयोग ने अपने सर्वेक्षण में 54 प्रश्नों वाली एक प्रश्नावली का इस्तेमाल किया था। इस बार आयोग इसमें और पहलुओं को शामिल करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, सर्वेक्षण वैज्ञानिक और पारदर्शी होना चाहिए और प्रश्नों को विशेषज्ञ समिति से परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, इस जाति सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य जाति और वर्ग के भेदभाव को समाप्त करना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। हम चाहते हैं कि यह देश

के लिए एक आदर्श बने। साफ है कि कांग्रेस सरकार इस सर्वे के जरिए बिहार चुनाव से पहले व्यापक संदेश देना चाहती है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यह निर्णय कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के एक औपचारिक प्रस्ताव के बाद लिया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में 7 करोड़ की अनुमानित आबादी का सर्वेक्षण करना है। इस सर्वेक्षण में 2024 की जाति गणना से प्राप्त जानकारी भी शामिल की जाएगी, जिसमें राज्य के 96 प्रतिशत लोगों को शामिल किया गया था और जिसके निष्कर्ष इस वर्ष की शुरुआत में प्रस्तुत किए गये थे। प्रक्रियागत बदलाव के तहत नया सर्वेक्षण एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटल रूप से किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों सहित लगभग 1.65 लाख गणनाकर्ता इस कार्य के लिए तैनात किए जाएंगे। प्रश्नावली को अंतिम रूप देने और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक उच्च-स्तरीय निगरानी समिति और एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

रमी की लत ने टीचर को बना दिया चोर, बुर्का पहनकर चुराए 8 लाख

अहमदाबाद, एजेंसी। अहमदाबाद के मेघानीनगर स्थित एक नर्सिंग कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल को 8 लाख रुपये की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इस मामले में उनकी दाहिनी आंख के पास एक तिल से सुराग मिला। सीसीटीवी फुटेज में बुर्का पहने एक महिला को चुपके से कॉलेज के तिजोरी से नकदी निकालते देखा गया और उस तिल ने उनकी पहचान उजागर कर दी। शाहिबाग की निवासी 42 साल की यह महिला ने पुलिस को बताया कि वह ऑनलाइन रम्मी की लत में इस कदर डूब गई थी कि कर्ज के जाल में फंस गई। इस कर्ज से उबरने और खेल जारी रखने के लिए उसने कॉलेज की तिजोरी से पैसे चुराने का रास्ता चुना। उसने 22 जुलाई की सुबह 6 बजे तिजोरी से 500 रुपये के नोटों की गड्डी निकाली, जिसमें कुल 8 लाख रुपये थे। मामला तब खुला जब कॉलेज के प्राचार्य को सुबह तिजोरी खाली मिली। उन्होंने तुरंत स्टाफ को इकट्ठा किया और पूछताछ शुरू की। हैरानी की बात यह थी कि उस समय चोर यानी वाइस प्रिंसिपल भी वहां मौजूद थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन पुलिस ने रातभर सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की और उस तिल ने सारा राज खोल दिया। सब-इंस्पेक्टर आर. एम. चावड़ा ने बताया, फुटेज में बुर्का पहने महिला की दाहिनी आंख के पास तिल देखकर हमें शक हुआ। अगली सुबह जब हमने वाइस प्रिंसिपल से पूछताछ की और वीडियो दिखाया, तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने शाहिबाग में उनके घर और उनके पास से 2.36 लाख रुपये नकद बरामद किए। बाकी 5.64 लाख रुपये? वह रातोंरात उनके ऑनलाइन गेमिंग वॉलेट में ट्रांसफर हो चुके थे। पुलिस ने उस वॉलेट को फ्रीज कर दिया है और बाकी रकम की बरामदगी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। मेघानीनगर पुलिस ने महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 (चोरी) के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही, धारा 306 के तहत क्लर्क या कर्मचारी द्वारा चोरी के लिए अतिरिक्त आरोप जोड़े जा रहे हैं। यह घटना न केवल कॉलेज के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक सबक है कि लत कितनी खतरनाक हो सकती है।

गुफा में मिली रूसी महिला नीना कुटिना के निर्वासन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को रूसी नागरिक नीना कुटिना के निर्वासन (डिपोर्टेशन) पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। 40 वर्षीय नीना इस महीने की शुरुआत में गोकर्ण के रामतीर्थ हिल की एक गुफा में अपनी दो बेटियों के साथ रहती हुई पाई गई थीं। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एस सुनील दत्त यादव की सिंगल बेंच ने की। उन्होंने कहा कि नीना कुटिना को भारत से जबरन बाहर भेजना उनकी बेटियों की सुरक्षा और कल्याण को खतरे में डाल सकता है। नीना की ओर से पेश अधिवक्ता बीना पिल्लई ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि (यूएनसीआरसी) का हवाला देते हुए दलील दी कि निर्वासन की प्रक्रिया बच्चों के सर्वोत्तम हित की अनदेखी करती है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार किसी भी निर्णय में बच्चों की भलाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यूएनसीआरसी के अनुच्छेद 3 के तहत, बच्चों को प्रभावित करने वाले सभी निर्णयों और कार्रवाइयों में उनके सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की

भलाई को ध्यान में रखते हुए इस निर्वासन आदेश पर पुनर्विचार जरूरी है। भारत सरकार की ओर से इस मामले में पेश हुए सहायक सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने अदालत को बताया कि बच्चों के पास वर्तमान में वैध यात्रा या पहचान दस्तावेज नहीं हैं। इस दलील के आधार पर, अदालत ने कहा कि इस स्तर पर तत्काल निर्वासन उचित नहीं है।

नीना कुटिना एक रूसी नागरिक हैं, जो अपनी दो बेटियों के साथ कर्नाटक के गोकर्ण में रामतीर्थ हिल की एक गुफा में रह रही थीं। पुलिस के अनुसार, नीना आठ साल पहले भारत में प्रवेश करने के बाद अपनी वीजा अवधि से अधिक समय तक भारत में अवैध रूप से रुकी रहीं। पूछताछ में नीना ने पुलिस को बताया कि वह गोवा से गोकर्ण इसलिए आई थीं ताकि आध्यात्मिक एकांत में रह सकें और प्रकृति के करीब जीवन बिता सकें। 9 जुलाई को गुफा में पाए जाने के बाद प्रशासन ने नीना और उनके बच्चों को टुमकुरु जिले के एक आश्रय गृह में भेज दिया,

ऐसे ही चला तो 2041 तक असम में बराबर होगी हिंदू-मुसलमान की आबादी: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

डिब्रूगढ़, एजेंसी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अगर राज्य में मौजूदा जनसंख्या वृद्धि की दर जारी रही, तो वर्ष 2041 तक हिंदू और मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग बराबर हो सकती है। उन्होंने यह बयान बुधवार को एक कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया।

सरमा ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, असम में कुल जनसंख्या का 34 प्रतिशत हिस्सा मुसलमानों का था, जिनमें से 31 प्रतिशत मुस्लिम वे हैं जो असम में बाहर से आकर बसे हैं, जबकि सिर्फ तीन प्रतिशत मुसलमान असम के मूल निवासी हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यदि पिछले दशकों के जनगणना आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या का विश्लेषण किया जाए, तो यह साफ़ दिखता है कि राज्य में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और अगर यही रफ्तार बनी रही तो 2041 तक हिंदू और मुस्लिम

आबादी लगभग 50:50 हो जाएगी। उन्होंने कहा, यह मेरा व्यक्तिगत अनुमान नहीं है, बल्कि जनगणना के आंकड़े और उनकी गणना यही संकेत दे रही है। मैंने सिर्फ वह दोहराया है जो सरकारी आंकड़े बताते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वर्ष 2001 में जब राज्य में कुल 23 जिले थे, तब 6 जिले मुस्लिम बहुल थे, जिनमें धुबरी, बरपेटा, नगांव, करीमगंज, हाइलाकांडी और गोलपारा शामिल थे। वर्ष 2011 की जनगणना तक राज्य में जिले बढ़कर 27 हो गए और इनमें से 9 मुस्लिम बहुल हो चुके थे, जैसे कि मोरीगांव, दारांग और बोंगाईगांव। मुख्यमंत्री के अनुसार, अब यह संख्या बढ़कर कम से कम 11 जिलों तक पहुंच चुकी है, हालांकि 2021 की जनगणना रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राज्य में चल रहे बेदखली अभियानों पर सवाल किया गया, तो मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की लगभग 29 लाख बीघा ज़मीन (करीब 10 लाख एकड़) पर अवैध कब्जे हैं। उन्होंने कहा, हम लगातार बेदखली अभियान चला रहे हैं, लेकिन इतनी ज़मीन को खाली कराना एक व्यक्ति के कार्यकाल से संभव नहीं है।

गुरुकुल में पढ़े छात्र करेंगे आईआईटी में रिसर्च, शिक्षा मंत्रालय की खास योजना

गुरुग्राम, एजेंसी। भारतीय पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति में प्रशिक्षित छात्र अब आईआईटी से शोध कर पाएंगे। शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ इंडियन नॉलेज सिस्टम डिविजन और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से सेतुबंध स्कॉलर स्कीम शुरू की गई है। पहली बार शुरू की गई यह योजना उन पारंपरिक विद्वानों के लिए है, जिन्होंने कम से कम पांच वर्षों तक किसी गुरु या गुरुकुल में रहकर भारतीय विद्याओं या कलाओं में गहन अध्ययन किया है। ऐसे 18 क्षेत्र चयनित किए गए हैं, जिसमें शोध करने का मौका मिलेगा। जिन छात्रों ने पारंपरिक पद्धति से अध्ययन किया है, लेकिन जिनके पास औपचारिक डिग्री नहीं है, वे अब अपनी विद्वत्ता प्रमाणित करके मान्यता प्राप्त डिग्री के साथ-साथ शोध भी कर पाएंगे। केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी ने कहा कि यह योजना पारम्परिक भारतीय विद्या और आधुनिक शिक्षा जगत के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेंगी। कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय में छात्रों का नामांकन पीजी या रिसर्च में होगा, लेकिन उनके अध्ययन का स्थल आईआईटी में होगा। आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मंडी और आईआईटी रुड़की से हमारा अनुबंध हुआ है। इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) डिविजन भी मदद करेगा, क्योंकि हमारा उनके साथ भी एमओयू है। कुलपति ने बताया कि 25 साल पहले आईआईआईटी हैदराबाद में इस तरह का प्रयोग किया गया था, जिसका मैं भी लाभार्थी हूं। मुझे वहां अध्ययन से एक नई दृष्टि मिली।

छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक, 3 लोगों को मार डाला; घर भी ढहा दिया

रायगढ़, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथी के हमले से 3 लोगों की मौत हो गई। 22 जुलाई की रात ग्राम गोसाईडीह और मोहनपुर में हथिनी और उसके शावक ने जमकर उत्पात मचाया है। गांवों के करीब हाथियों की मौजूदगी से दहशत है। हाथियों का दल रोजाना गांवों में पहुंचकर फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन अमला सिर्फ मुनादी करके और जंगलों में नहीं जाने की अपील करके खामोश है। ताजा मामला लैलूंगा रेंज का बताया जा रहा है।

मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात लैलूंगा के गोसाईडीह गांव में हाथी ने पांच साल के बच्ची को पटक कर मार डाला। वह घर में सोई थी, तभी हाथी आ धमका। मकान को तोड़ दिया और बच्ची को सूंड से उठाकर पटक दिया। इधर अंगेकेला गांव में भी एक महिला को हाथी ने खेत में कुचल कर मार डाला। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के करीब एक हाथी अपने शावक के साथ विचरण कर रहा है। रात होते ही उसी हाथी ने गांव में घुसकर उत्पात मचाया है।

एक और घटना लैलूंगा रेंज के मोहनपुर गांव में घटी है। हाथी के दल ने घर के दीवार को धक्का देकर गिरा दिया। इस दौरान मलबे की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हाथी के हमले से तीन लोगों की मौत की खबर के गांव के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी गांव पहुंचे हैं। पुलिस की भी सूचना दी गई है। मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया गया है। डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय के मुताबिक इन दिनों रायगढ़ जिले में कुल 136 हाथी विचरण कर रहे हैं, जिसमें धमरजयगढ़ में 88 हाथी तो रायगढ़ वन मंडल में 48 हाथियों की मौजूदगी है। सर्वाधिक हाथी बाकारूमा रेंज के तेजपुर में 25, छाल रेंज के बेहरामार में 25, कापू रेंज के कूमा बीट में 13, रायगढ़ वन मंडल के कांटाझरिया बीट में 16, तमनार रेंज के हिंझर में 13, घरघोड़ा रेंज के कटंगडीह में 10 हाथियों के अलावा अलग-अलग बीट में कुछ हाथियों की मौजूदगी है।

मस्जिद का सियासी इस्तेमाल शरीयत के खिलाफ, अखिलेश की बैठक पर देवबंदी उलमा भड़के

रामपुर , एजेंसी। सपा चीफ अखिलेश यादव और रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी का एक मस्जिद के अंदर बैठक का वीडियो वायरल होने के बाद सियासत तेज है। इस बीच जमीयत दावतुल मुसलीमीन के संरक्षक कारी इस्हाक गोरा ने अखिलेश यादव और सपा नेताओं द्वारा मस्जिद में बैठक करने पर रोष व्यक्त किया। भड़के देवंबदी उलमा कारी इस्हाक गोरा कहा कि मस्जिद को सियासी मंच बनाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। कारी इस्हाक गोरा बुधवार को जारी बयान में कहा कि रामपुर से सपा सांसद मौलाना मोहिब्बुल्ला नदवी, पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कुछ महिला प्रतिनिधियों के साथ एक मस्जिद के अंदर इमाम के मुसल्ले के करीब बैठक की। जिसकी वीडियो और तस्वीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस पर दुनियाभर के मुसलमान प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है, इबादत की जगह हैं, इसे सियासी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना शरीयत के सरासर खिलाफ है। मस्जिदें इबादत, तिलावत और रूहानी सुकून का मरकज हैं न कि सियासी बैठकों का।

जामा मस्जिद में समाजवादी पार्टी के सांसदों की मौजूदगी ने सियासी हलकों में नया विवाद खड़ा कर दिया है। रामपुर से सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी की मेजबानी में हुई इस बैठक में सम्भल से सांसद डॉ. जियाउर्रहमान बर्क समेत कई अन्य नेता शामिल रहे। तस्वीरों में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव भी पारंपरिक साड़ी में नजर आईं, जिसके बाद मस्जिद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने इसे धार्मिक स्थल का राजनीतिक इस्तेमाल करार देते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं, मौलाना नदवी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह मुलाकात धार्मिक सौहार्द के दायरे में थी, औपचारिक बैठक नहीं थी। भाजपा बेवजह मुद्दा बना रही है। इस मसले ने अब उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्मी ला दी है, जहां रामपुर और सम्भल जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में यह बहस और तेज हो गई है।

समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ. जियाउर्रहमान बर्क ने संसद की मस्जिद को लेकर उठे विवाद पर स्पष्ट किया है कि वहां कोई राजनीतिक बैठक नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि मस्जिद के भीतर सिर्फ धार्मिक चर्चा होती है, राजनीतिक बैठकें नहीं। भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बर्क ने कहा कि यह सब जानबूझकर रचा गया प्रोपेगंडा है। सांसद बर्क ने दो टूक कहा कि उनके पास राजनीतिक बैठक के लिए पर्याप्त स्थान हैं, मस्जिद को राजनीति से जोड़ना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, भाजपा ध्यान भटकाने के लिए नए-नए मुद्दे उछाल रही है। रामपुर सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी की उस मांग का जिक्र करते हुए बर्क ने कहा कि उन्होंने ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मस्जिद में आने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों को निशाना बनाया जा रहा था, तब भाजपा खामोश थी। आज वही लोग धर्म की राजनीति करके खुद को गौरवशाली साबित करने में जुटे हैं।

सपा के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन ने कहा कि मंदिर और मस्जिद में हर वर्ग का व्यक्ति जा सकता है। अखिलेश यादव मस्जिद गए तो इसमें गलत क्या है? भाजपा इसे बेवजह राजनीतिक रंग दे रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा किसावन के पावन माह में मस्जिद में बैठक कर सियासत करना हिंदू समाज की आस्था पर आघात है। सपा का नाम नमाजवादी पार्टी ही ठीक रहेगा। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बताया कि हम दिल्ली की मंत्री और वक्फ बोर्ड से मांग करेंगे कि मोहिबुल्लाह नदवी को इमाम पद से हटाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

हरियाणा में बड़े पैमाने पर चल रहे गोमांस के गोरखधंधे का खुलासा

नूंह, एजेंसी। हरियाणा के नूंह जिले में बुधवार को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक गांव के कई घरों पर छापा मारा और वहां से कथित तौर पर सात क्विंटल से ज्यादा गोमांस जब्त किया। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि जिन लोगों के मकानों से गोमांस की बरामदगी हुई है, वे अपने घरों से आस-पास के गांवों और शहरों में मांस की आपूर्ति कर रहे थे, यहां तक कि आरोपी मोटरसाइकिल से भी लोगों के घरों तक उसकी डिलीवरी कर रहे थे। इस मामले को लेकर पुलिस की गोहत्या विरोधी टीम ने एक व्यक्ति और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है, जबकि सात लोग फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने बताया कि जांच में मांस के गाय का होने की पुष्टि हुई और इसके लिए आसपास के राज्यों से गायें चुराकर यहां लाया गया था। इसके साथ ही पुलिस ने गोमांस की डिलीवरी में इस्तेमाल होने वाली आठ बाइक भी इलाके से ज़ब्त की हैं। मामले की जानकारी देते हुए सीएस स्टाफ के प्रभारी इंस्पेक्टर राजबीर ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बुधवार तड़के तीन बजे रिठथ गांव में वक्की उर्फ वकील के घर पर छापा मारा, जिससे अंदर मौजूद लोग इधर-उधर भागने लगे। उसी छापेमारी में वक्की उर्फ वकील और उसके बेटे नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया।

कासिम कृष्ण बनकर यूपी के मंदिर में करा रहा था पूजा पाठ

मेरठ, एजेंसी। बिहार का कासिम एक साल से यूपी में मेरठ के दादरी स्थित मंदिर में कृष्ण बनकर पूजापाठ करा रहा था। आरोपी पर कुछ लोगों को शक हुआ तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी कासिम को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। दौराला थानाक्षेत्र के दादरी गांव में प्राचीन शिव मंदिर है। एक साल पहले एक व्यक्ति गांव आया और अपना नाम कृष्ण पुत्र संतोष निवासी दिल्ली बताते हुए मंदिर में रहने के लिए ग्रामीणों से अनुमति मांगी। चूंकि मंदिर में कोई पुजारी नहीं थे, इसलिए कृष्ण को मंदिर में रहने की अनुमति दे दी गई।

इसके बाद से कथित कृष्ण मंदिर में रहकर पूजा-अर्चना करने लगा। कुछ समय पूर्व गांव के लोगों ने शक होने पर कृष्ण का आधार कार्ड मांगा। इस दौरान आधार कार्ड लाने की बात कहकर 15 दिन के लिए कृष्ण लापता हो गया था। बाद में मंदिर में आकर दोबारा से पूजन करने लगा। हस्तरेखा देखने को लेकर 15 दिन पहले भी कुछ ग्रामीण से कृष्ण की कहासुनी हो गई, जिसके बाद वह मंदिर छोड़कर कहीं चला गया

था। बुधवार को शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा को लेकर मंदिर पर ग्रामीणों ने भंडारे किया हुआ था। इसी दौरान वह आयोजित भंडारे में पहुंचा और मंदिर के कमरे में रखा कुछ सामान निकालने लगा। ग्रामीणों ने कृष्ण पर चोरी का आरोप लगाकर पकड़ लिया और मुस्लिम होने का आरोप लगा दिया। इसी दौरान कुछ ग्रामीण ने आरोपी की धोती खोल दी और पहचान कर पुलिस को बुला लिया। आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना नाम कासिम निवासी बिहार बताया, जिस पर हंगामा हो गया। बिहार का कासिम एक साल से मेरठ के दादरी स्थित मंदिर में कृष्ण बनकर पूजा पाठ करा रहा था, जबकि जांच और पूछताछ के बाद पता चला कि उसका पिता मोहम्मद अब्बास ग्राम कोली रायपुर सीतामढी बिहार में मौलवी है। पूछताछ में कासिम ने पुलिस को बताया कि उसका पिता मोहम्मद अब्बास मौलवी है। वह छह भाई-बहनों में तीसरे नंबर का है। उसने दिल्ली के मंदिरो में रहकर पूजा पाठ और मंत्रों का उच्चारण सीखा। दिल्ली में उसने अपने हाथ पर कृष्ण लिखवाया था। पूछताछ करने पर वह अपना नाम कृष्ण और पिता का नाम संतोष बताता था।

भीड़ ने कासिम को बंधक बना लिया और मारपीट कर दी। इस दौरान कासिम ने बताया कि उसने हिंदु धर्म अपना रखा है। पिछले कई सालों से वह संतों के साथ ही मंदिरों में रहा है। इसी के चलते हाथ पर भी अपना नाम कृष्ण ही लिखा रखा है। सूचना पर आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और कासिम को दबोच लिया।

आरोपी को थाने लाया गया और पूछताछ की गई। इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने अपना नाम कासिम पुत्र मोहम्मद अब्बास मौलवी निवासी ग्राम कोली रायपुर सीतामढी बिहार बताया है। इस संबंध में बिहार पुलिस को सूचना भेजी गई है और सत्यापन कराया जा रहा है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह 20 साल पूर्व उत्तर प्रदेश में आया था। पहले दिल्ली के मंदिरो में पूजा पाठ करता था। एक साल पहले दादरी गांव के मंदिर में आया था। पुजारी आधार कार्ड नहीं दिखा पाया, जिसे लेकर जांच की जा रही है। फिंगरप्रिंट की मदद से आधार कार्ड निकलवाया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी कासिम पुलिस सत्यापन के समय भी अपना नाम कृष्ण बताता था। बताया कि चूंकि मामला मंदिर के पुजारी का था, इसलिए पुलिसकर्मी ज्यादा दबाव नहीं बनाते थे और आधार कार्ड नहीं देखा। पूर्व में ही आधार कार्ड देख लिया होता तो खुलासा हो जाता। वहीं, कासिम से पूछताछ के लिए खुफिया विभाग की टीम भी पहुंची है। पुलिस सत्यापन के प्रयास में लगी है और इसके बाद ही सारी बातों से पर्दा उठ सकेगा। फिलहाल आरोपी कासिम पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

रोडवेज बस ने पीआरवी को मारी टक्कर, दो पुलिसकर्मी घायल

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷। थाना लोधा क्षेत्र में एक रोडवेज बस ने गश्त कर रही पीआरवी पुलिस की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना अलीगढ़-पलवल हाईवे पर गांव चिकावती के समीप हुई। पीआरवी 0742 गश्त कर रही थी, इसी दौरान तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पुलिसकर्मी वीरेश और सुरजीत घायल हो गए। थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल पुलिसकर्मी वीरेश ने बताया कि वे देर रात गश्त कर रहे थे। अचानक जोरदार आवाज के साथ उनकी गाड़ी को टक्कर मारी गई। हादसे के बाद रोडवेज चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है।

मेडीकल में उपचार के दौरान बिल्डर लाडले की हुई मौत

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷। सिविल लाइंस इलाके में जामिया उर्दू रोड पर 21 जुलाई दोपहर स्कूटी सवार बिल्डर जुल्फिकार उर्फ लाडले खां बेटी को कोचिंग से लेने जा रहे थे। उन पर बुलट सवार दो हमलावरों ने चार गोलियां मारीं थीं। गंभीर हालत में उन्हें जेएन मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। वहीं पर बिल्डर लाडले ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मूल रूप से छर्रा कोठी मोहल्ला के पेशे से बिल्डर जुल्फिकार खान उर्फ लाडले परिवार के साथ सिविल लाइंस क्षेत्र के मेडिकल रोड पर स्थित रिफा कांप्लेक्स में रहते थे। उनकी जकरिया मार्केट पर दवा की दुकान भी है। 21 जुलाई दोपहर करीब 1.45 बजे वे जामिया उर्दू के पीछे की मस्जिद से नमाज पढ़कर स्कूटी पर सवार होकर बेटी को लेने कोचिंग जा रहे थे। एडीएम कंपाउंड के सहारे पहुंचते ही पीछे से आए बाइक सवार दो हमलावरों ने उन्हें स्कूटी में टक्कर मारकर रोका। फिर पहली गोली पीछे से पीठ में मारी। इसके बाद उन्हें ताबड़तोड़ तीन गोलियां और मारी गईं। साथ में दो राउंड हवाई फायर भी किए गए। मौके पर कुल छह राउंड फायर हुए। हमले में दो गोली पेट और सीने पर एक कनपटी पर व एक सीधे बाजू में लगी। हमले में लाडले बिल्डर वहीं लहूलुहान हालत में गिर गए। सूचना पर इलाका पुलिस व परिचित भी पहुंच गए। आनन-फानन उन्हें टिर्री के जरिये मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। जहां उनका उपचार जारी था। लाडले की मौत हो गई।

स्मैक के साथ अभियुक्त किया गिरफ्तार

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷। जनपद में अपराध, अपराधियों पर नियंत्रण वांछित व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शराब, चरस, गांजा की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना क्वार्सी पुलिस ने अभियुक्त बिट्टू उर्फ शोएब पुत्र जियाउद्दीन निवासी गली नं0 6 कबीर कालोनी लाइन पार थाना सिविल लाइन हाल निवासी रामनगर थाना क्वार्सी अलीगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष को 20 ग्राम स्मैक सहित किला रोड नगला पटवारी से गिरफ्तार किया।

तमंचा कारतूस सहित अभियुक्त गिरफ्तार

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷। जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र कारतूस रखने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गाँधीपार्क पुलिस टीम ने कामाख्या सिटी के अन्दर टी पाइन्ट पर पेड़ के नीचे से अभियुक्त अवनीश कुमार उर्फ मामू पुत्र रामवीर सिंह निवासी माली नगला हरि सिंह की ट्यूबेल के पास थाना गाँधीपार्क अलीगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष को एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया।

पुलिस ने दो लुटेरे किये गिरफ्तार

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷। जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक देहात के निर्देशन, क्षेत्राधिकरी अतरौली के पर्यवेक्षण में थाना हरदुआगंज पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त बादल पुत्र हबीब खां निवासी ग्राम मोरथल थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ व रवि पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी इस्कॉन मन्दिर के पास कस्बा हरदुआगंज थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ को माछुआ पुल से बरौठा पुल की तरफ 20 मीटर आगे से गिरफ्तार किया गया। थाना हरदुआगंज पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही एवं विभिन्न माध्यमों से सूचना संकलन, सीसीटीवी फुटेज इत्यादि एवं अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त बादल व रवि को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से लूटी गयी मोटर साईकिल यू0पी0 81 डी0एल0 6873, एक मोबाइल फोन सैमसंग, एक चाकू बरामद किये।

पुलिस लाइन में साइबर सेमिनार का हुआ आयोजन

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷

गुरूवार को पुलिस अधीक्षक अपराध के नेतृत्व में जनपदीय साइबर सेल टीम द्वारा नवीन रिजर्व पुलिस लाइन छेरत में साइबर जागरुकता सेमिनार आयोजित की गई।

जिसमें प्रशिक्षणरत रिक्रूट आरक्षी उ0प्र0 नागरिक पुलिस को वर्तमान में होने वाले विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों जैसे लोन एप के माध्यम से फोन का एक्सेस लेकर पैसे मांगना, परिचित बनकर खाते मे पैसे डालने का बहाना बनाकर ऑनलाइन ठगी करना, लॉटरी व उपहार का लालच देकर आनलाइन ठगी करना, मोबइल सिम व खाते को अपडेट करने के बहाने खाते व एटीएम की जानकारी लेकर आनलाइन ठगी करना, गूगल से कस्टमर केयर का नम्बर सर्च कर बात करने पर ठगी होना।

फेसबुक व व्हाट्सएप पर दोश्ती कर वीडियो कॉल के द्वारा अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना, ओएलएक्स तथा फेसबुक पर सामान बेचने व खरीदने के बहाने से ठगी करना के बारे मे जानकारी दी।

साइबर अपराध से बचने के तरीके जैसे किसी अनजान नम्बर से परिचित बनकर आने वाली फोन कॉल पहले अपने फोन से उक्त परिचित से बात कर लेने से इस प्रकार की घटना से बचा जा सकता है तथा अपने फोन पर सिम व खाते को अपडेट कराने वाली फोन कॉल से बचें।

यदि आपको कभी भी किसी कम्पनी के कस्टमर केयर नं0 की आवश्यकता होती है तो सदैव उस कम्पनी की वाश्तविक साइट पर जाकर फोन न0 प्राप्त करें।

साइबर अपराधियों द्वारा आवाज को कॉपी कर व वीडियो कॉल पर परिचित का चेहरा लगाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सगे सम्बन्धियों से साइबर ठगी की जाती है, साइबर जागरूकता कार्यक्रम में साइबर अपराधों से सम्बन्धित जानकारी भी दी गयी।

जिससे बचने के लिए सम्बन्धी व्यक्ति से बात कर पूर्ण पुष्टि कर लेनी चाहिए तथा साइबर ठगों द्वारा नकली पुलिस अधिकारी बनकर पीड़ित को फोन पर बताया जाता है कि आपके नाम से एक शिकायत दर्ज हुई है।

झूठे मामले को लेकर पीड़ित को पहले काफी डराया धमकाया जाता है इसके बाद घर से बाहर निकलने से मना कर देते है और यह कहते है कि आपको डिजीटल अरेस्ट किया जाता है।

पुलिस द्वारा इस प्रकार डिजिटल अरेस्ट नहीं किया जाता है अगर किसी के पास ऐसी कॉल आती है तो वह फ्रॉड काल है इसे इग्नोर करें। इस प्रकार वर्तमान समय में होने वाली साइबर अपराध की घटनाओं से बचा जा सकता है।

यदि साइबर अपराध की घटना हो जाती है तो इसकी सूचना तुरन्त साइबर अपराध हेल्पलाइन नं0 1930 पर कॉल करें तथा इसकी शिकायत साइबर क्राइम पुलिस पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर करने के बारे में बताया।

डिजाइन आर्क में भीषण आग, दमकलकर्मी की तत्परता से हादसा टला

✷एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

दिल्ली सीमा के नजदीक थाना कौशांबी इलाके वैशाली की डिजाइन आर्क सोसाइटी में गुरुवार को भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि आग सेक्टर-5 स्थित एल-101 नंबर फ्लैट में लगी थी, जो फ्लैट निवासी कपिल गर्ग के नाम पर है।

घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग हरकत में आ गया और प्रभारी अधिकारी के नेतृत्व में तीन दमकल वाहन मौके के लिए रवाना किए गए।

घटनास्थल पर पहुंचने के बाद दमकलकर्मियों ने पाया कि आग इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट में भयानक रूप ले चुकी थी।

आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला।

एक टीम ने बालकनी से होज पाइप फैलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, वहीं दूसरी टीम ने फ्लैट का गेट तोड़ते हुए एक और होजलाइन अंदर फैलाई और अंदरूनी हिस्सों में लगी आग को बुझाने में जुट गई।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद के निर्देशन में फायर यूनिट ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से पहले नियंत्रित कर लिया।

अवैध धर्मांतरण की जांच की आंच पहुंची गाजियाबाद, क्राइम ब्रांच प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी निलंबित

✷एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार आरोपितों से पुलिस की पूछताछ में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अवैध धर्मांतरण की जांच की आंच अब गाजियाबाद तक पहुंच गई है।

मेरठ पुलिस की एक रिपोर्ट के बाद गाजियाबाद के क्राइम ब्रांच प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को निलंबित कर दिया गया है। इंस्पेक्टर सिद्दीकी का निलंबन मेरठ से वर्ष 2019 में गायब हुई एक लड़की के धर्मांतरण के मामले में शिकायत करने पर पीड़ितों को धमकाने और छांगुर बाबा के सहयोगी बदर सिद्दीकी को बचाने के आरोप में की गई है।

दरअसल, वर्ष 2019 में अब्दुल रहमान सिद्दीकी मेरठ में सिविल लाइन थाना के प्रभारी थे। एक युवती के परिजनों ने आरोप लगाया है कि अपनी लड़की के अपहरण और धर्मांतरण की शिकायत लेकर छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन के सहयोगी बदर सिद्दीकी के खिलाफ कंप्लेंट लेकर थाना प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी के पास गए थे, तब उन्हें थाने से डरा धमका कर भगा दिया गया था। उनकी गुमशुदगी तक दर्ज नहीं की गई थी। इस संबंध में मेरठ पुलिस ने एक रिपोर्ट गाजियाबाद पुलिस को भेजी थी।

इसके बाद गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड ने क्राइम ब्रांच प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को निलंबित कर दिया है। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि मेरठ से वर्ष 2019 में गायब हुई उनकी लड़की के धर्मांतरण के मामले में शिकायत करने पर उन्हें धमकाया गया और चुप रहने को कहा गया।

साथ ही कार्रवाई भी नहीं की। अब इस मामले की भी जांच शुरू कर दी गई है। इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी लंबे समय से गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच में तैनात हैं।

इंस्पेक्टर सिद्दीकी को कई बड़े मामलों के खुलासा करने पर कई पदक भी मिल चुके है।

महिला अभियुक्ता सहित दस गोकश किये गये गिरफ्तार

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन द्वारा संगठित गैंग बनाकर जघन्य अपराधों में लिप्त शातिर हार्डकोर अपराधियों के विरूद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कड़ी निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तारी हेतु दिये गये।

निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी बरला गर्वित सिंह के कुशल पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बरला अरुण कुमार के नेतृत्व में थाना बरला पुलिस टीम ने मुखविर की सूचना पर गोकशी में वांछित 09 अभियुक्तगण आदिल पुत्र मैंहदी हसन उर्फ बड़े निवासी पिलखना थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ उम्र 29 वर्ष, मेंहदी हसन पुत्र बुन्दा खाँ नि0 पिलखना थाना बरला जनपद अलीगढ़ उम्र 55 वर्ष, मेहरूउददीन पुत्र रहमान खाँ निवासी सतरापुर थाना छर्रा जनपद अलीगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष, फिरोज पुत्र रज्जूखाँ निवासी सतरापुर थाना छर्रा जनपद अलीगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष, साहिल पुत्र शमशेर खाँ निवासी नगला बादशाह थाना छर्रा जनपद अलीगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष, इसरार पुत्र यामीन खाँ निवासी निवासी नगला बादशाह थाना छर्रा जनपद अलीगढ़ उम्र 34 वर्ष, मुसीर पुत्र बुन्दा खाँ उम्र 30 वर्ष निवासी पिलखना थाना बरला जनपद अलीगढ़, मुहीद पुत्र बुन्दा खाँ उम्र 34 वर्ष निवासी पिलखना थाना बरला जनपद अलीगढ़, मुफीद पुत्र बुन्दा खाँ उम्र 38 वर्ष निवासी पिलखना थाना बरला जनपद अलीगढ़ व महिला अभियुक्ता व आसमा पत्नी मुहीद उम्र 27 वर्ष निवासी पिलखना थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ को अकराबाद व बरला के बॉर्डर पर काली नदी के पुल से गिरफ्तार किया।

अभियुक्तगण द्वारा विगत 04 जनवरी 2025 को थाना बरला क्षेत्रांतर्गत कस्बा पिलखना स्थित दुकान में गोमांस काटकर बिक्री हेतु एक स्विफ्ट कार से लेकर जा रहे थे।

तभी पुलिस टीमों ने चेकिंग के दौरान बरला मोड़ पर उपरोक्त अभियुक्तों से गोमांश बरामद किया गया था एवं जिसके सम्बन्ध में थाना बरला पर गोवध निवारण अधिनियम व बीएनएस बनाम 18 नफर पंजीकृत किया गया था। चार अभियुक्तों को उसी समय गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था एवं गोकशी के अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित पिलखना स्थित सम्पत्ति कीमत करीब दो करोड़ बीस लाख व स्विफ्ट कार को पूर्व में ही धारा 14(1) के तहत जब्त किया गया।

यूपी बोर्ड : जिले के 562 विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट परीक्षाएं कल, तैयारी पूरी

दो पालियों में हाईस्कूल के 82 और इंटरमीडिएट के 482 विद्यार्थी देंगे परीक्षा

✷एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

जिले में यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट परीक्षाएं 26 जुलाई को होंगी। परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। परीक्षा में 562 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षाओं की तरह इन परीक्षाओं के लिए भी कड़ी सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की वर्ष 2025 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा पहले 19 जुलाई को होनी थी, लेकिन कांवड़ यात्रा के चलते परीक्षाओं की तिथि बदलकर 26 जुलाई कर दी गई।

जिले में कंपार्टमेंट परीक्षाएं केवल एक ही दिन होगी। परीक्षा के लिए हाईस्कूल के 82 और इंटरमीडिएट के 480 छात्र-छात्राओं समेत कुल 562 छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में होगा। सुबह 8.30 बजे से 11.45 बजे के बीच हाईस्कूल की परीक्षा होगी।

वहीं, दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.15 बजे के बीच इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। परीक्षा का आयोजन विजय नगर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज को में होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि केंद्र पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबश्त किए गए हैं।

परीक्षा की भी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सीसीटीवी कैमरे से लेकर वॉयस रिकॉर्डर तक सभी इंतजाम किए जाएंगे। डबल लॉक अलमारी में प्रश्न पत्रों की सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जबकि प्रवेश पत्र दो दिन पहले ही जारी हो गए हैं।

करोड़ों की ठगी के आरोपी अभिषेक गुप्ता व हिमांशु की गिरफ्तारी की मांग

✷ एनसीआर टुडे. नजीबाबाद ✷

पीड़ित लोगों ने क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद से मुलाकात कर फरार चल रहे हैं अभिषेक गुप्ता व हिमांशु चौहान की गिरफ्तारी की मांग की। कालोनीयों मै प्लॉट दुकान देने के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ थाना मंडावली में गंभीर धाराओं में तीन मुकदमे दर्ज हुए 25 दिन से ज़यिादा हो गए।

आसिम जलाल ओर शावेज़ को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मगर अभी भी अभिषेक गुप्ता व हिमांशु चौहान खुले आम घूम रहे हैं।

पीड़ितों ने आरोप लगाते हुए कहा कि थाना मंडावली पुलिस फरार आरोपियों से हमसाज़ होकर उन्हें बचाना चाहती है और पुलिस ने उन्हें इतना मौका दे दिया है कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपने बचाव में स्टे ले रहे हैं।

महादेवपुरम के नाम से काटी जा रही तीन कॉलोनियों व आदि कलोनीयों में सेंकड़ो लोगों के साथ फर्जी दशतावेज के आधार पर छल कर करीब 8 करोड़ की ठगी करने वालों पर पुलिस इतनी मेहरबान है।

पहले 2 महीना तक पीड़ित सभी अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाते रहे। जब जनपद से इंसाफ ना मिला तो पीड़ितों ने बिजनौर से बाहर निकल आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए।

16 जून 25 को आरोपियों द्वारा मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिसका प्रार्थना पत्र थाना मंडावली में दिया गया था

उस प्रार्थना पत्र पर भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने थाना अध्यक्ष मंडावली पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह पीड़ितों के सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। पीड़ितों ने हिमांशु व अभिषेक गुप्ता के खिलाफ ठोस सबूत दिए हैं मगर थाना अध्यक्ष ने उनको माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं रखा।

पीड़ितों ने कहा कि तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी न हुई तो सभी पीड़ित आईजी और डीआईजी के समक्ष अपनी फरियाद रखेंगे। उन्होंने कहा कि जेल में बंद आसिम जलाल से जुड़े लोग जान से मारने मुकदमा वापस लेने तथा फर्जी मुकदमे में फसाने की धमकी दे रहे हैं।

हमें डर है कि पीड़ितों मै से किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। गिरफ्तारी की की मांग करने वालों में ओम सिंह वीर सिंह सोमपाल चौधरी, पंकज कुमार, अमरपाल सिंह, विपुल कुमार चौधरी, उस्मान, इमरान, वीरेंद्र शर्मा, सुमन आरती आदि मौजूद रहे।

पुलिस अब गश्त नहीं करती, बाजार में लगता है जाम

एनसीआर टुडे. दनकौर। पुलिस अब गश्त नहीं करती है। इस वजह से मुख्य बाजार में जाम लगता है। बिहारीलाल और दीनदयाल समेत कई चौराहों पर वाहन चालक अक्सर फंस जाते हैं। इससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। ये बातें यहां के व्यापारियों ने बृहस्पतिवार को आयोजित संवाद कार्यक्रम में कहीं।

व्यापारियों ने कहा कि बाईपास की करीब 300 मीटर सड़क वर्षों से टूटी है। धनौरी रोड पर लगने वाले शुक्रवार के बाजार से जाम लगता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं को फिर से चालू किया जाए। यहां सुविधा कम होने के कारण लोगों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है।

छात्रा आत्महत्या केस : जेल में प्रोफेसरों से पूछताछ करेगी शारदा विश्वविद्यालय की जांच समिति

✷ एनसीआर टुडे. ग्रेटर नोएडा ✷

ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा विश्वविद्यालय में बीडीएस की छात्रा के आत्महत्या मामले में आज एक अहम मोड़ आ सकता है। विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच समिति प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से पूछताछ करने जा रही है, जो इस मामले में फिलहाल जेल में बंद हैं। इसके लिए समिति ने संबंधित थाने की पुलिस से अनुमति मांगी है।

आंतरिक जांच समिति को अनुमति मिलते ही वे जेल जाकर आरोपियों से पूछताछ करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट तैयार कर पुलिस को सौंपेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गठित इस समिति को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि वह पूरे घटनाक्रम की निष्पक्षता से जांच कर अपनी रिपोर्ट जल्द प्रश्तुत करे। माना जा रहा है कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कुछ और लोगों पर भी कार्रवाई संभव है।

उधर, मृतका के परिजन आज शारदा विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। उनका कहना है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की, तो वे बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। परिजनों का आरोप है कि पहले भी इस मामले में कई बार अनदेखी हुई है और अब तक केवल नाममात्र की कार्रवाई की गई है। छात्रा की आत्महत्या के बाद विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई बार प्रदर्शन किया था और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग उठाई थी।

जनहित की सेवा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : मण्डलायुक्त

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷

मण्डलीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए मण्डलायुक्त श्रीमती संगीता सिंह ने कहा कि जनसेवा में संलग्न अधिकारियों को आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में लापरवाही और समन्वयहीनता स्वीकार नहीं की जाएगी।

कमिश्नरी सभागार में आयोजित जून माह की प्रगति समीक्षा बैठक में अलीगढ़ जनपद की रैंकिंग में सुधार न होने पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि "ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इच्छाशक्ति और कर्तव्यनिष्ठा से पूरा न हो सके। आवश्यकता केवल संकल्प लेने की है।''

उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को सर्वोपरि रखें। शासन की योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिनके लिए वे बनाई गई हैं, यह प्रत्येक अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

मण्डलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन व जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निश्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा ''जनशिकायतें शासन की प्राथमिकता में हैं, इनकी अनदेखी सीधे तौर पर जनविश्वास को आघात पहुंचाती है''। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों व विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय और सामंजस्य के साथ कार्य करते हुए मण्डल की विकास रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा।

बैठक में अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज जनपद के जून माह के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। मण्डलायुक्त ने मई और जून की रैंकिंग की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए विभागवार प्रगति की विश्तार से समीक्षा की और लक्ष्य प्राप्ति में पिछड़ने वाले विभागों को सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। मई माह में अलीगढ़ 58, एटा 67, हाथरस 27 और कासगंज 70 वें स्थान पर था। वहीं जून माह में अलीगढ़ 58, एटा 33 , हाथरस 22 और कासगंज 58 वें स्थान पर है।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि मण्डल में 8 वृहद गौसंरक्षण केंद्र निर्माणाधीन हैं। एडी पशुपालन ने बताया कि प्रत्येक गौ संरक्षण केंद्र में लगभग 500 गौवंश संरक्षित होंगे। उन्होंने बताया कि मण्डल में 226 गौसंरक्षण केंद्र में 51162 गौवंश संरक्षित हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण में पुनः सत्यापन के उपरांत लक्षित परिवार 191 के सापेक्ष 143 के आवेदन कराए गए हैं। मण्डल में 633 परिवारों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।

आयुक्त ने निर्देश दिए कि अंत्योदय कार्ड धारक एवं 70 प्लस आयु वर्ग के बुजुर्गों के शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। सभी 31 पैरामीटर पर कश्तूरबा गांधी विद्यालयों की मरम्मत एवं कायाकल्प करने के निर्देश दिए गए। परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प में विद्युतीकरण, बाउंड्रीवाल निर्माण, फर्नीचर उपलब्धता की समीक्षा में जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जननी सुरक्षा योजना में 7849 संस्थागत प्रसव के सापेक्ष मात्र 241 को 48 घण्टे में योजना का लाभ दिया गया। अपर निदेशक स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया कि समय से लाभ दिलाना सुनिश्चित कराएं। सभी डीएम सीएमओ को निर्देशित किया गया कि अभियान चलाकर जिलों में संचालित हॉस्पिटल के पंजीकरण एवं विभिन्न अनापत्ति प्रमाणपत्र जाँच लिए जाएं। मंडल में 1191261 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाई जानी है, जिसके सापेक्ष 596664 बनाई जा सकीं है।

मण्डल में 35282 समूह गठित हैं, 15514 को विगत वर्ष बैंक क्रेडिट लिंकेज दिया गया और इस वर्ष 3568 को दिया जाना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 8000 के सापेक्ष 7725 आवेदन भेजे गए। 1857 पर स्वीकृति के सापेक्ष 1609 को लोन दिया गया।

कमिश्नर ने बैंकर्स को उदारतापूर्वक लोन उपलब्ध कराने के साथ विभाग को अस्वीकृत आवेदनों पर विशेष निगाह रखने के निर्देश दिए। मण्डल में 71.71 प्रतिशत ग्राम ओडीएफ प्लस घोषित हो गए हैं। मंडलायुक्त ने प्रत्येक जिले से 5-5 ग्राम का सत्यापन करने के निर्देश दिए। मण्डल में 544 डिजिटल लाइब्रेरी तैयार किए जाएंगे, जिसमें अलीगढ़ में 204, एटा में 121, हाथरस में 116 और कासगंज में 103 डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित होंगी। उचित दर दुकानों की रिक्तता को समाप्त किया जाए। मण्डल में 5 दुकानें निलंबित, 15 रिक्त हैं।

मण्डल में 515 मॉडल उचित दर की दुकानों का निर्माण कराया जाना है। 127 बन चुकी हैं, 92 पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। सड़कों की खराब स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आयुक्त ने लोनिवि चीफ को निर्देशित किया कि कार्य योजना तैयार रखें और बरसात समाप्त होते ही सड़कों की मरम्मत करते हुए गड्ढ़ा मुक्त कराएं। विद्युत चीफ पंकज अग्रवाल को निर्देशित किया गया कि अप्रिय दुर्घटना से पूर्व झूलते विद्युत तारों को दुरुश्त कराएं।

बैठक में नदियों के पुनरोद्धार, वृक्षारोपन, भूमिगत जल श्तर में बढोत्तरी, संचारी रोग नियंत्रण, पीएम आवास, मुख्यमंत्री आवास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में चारों जिलों के डीएम, सीडीओ, संयुक्त विकास आयुक्त मंशाराम यादव, डीएफओ नवीन प्रकाश एवं मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे।

संपादकीय

सड़क और संसद दोनों सूनी रखने की चाल

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बुधवार को सदन में नारेबाजी कर रहे और पोस्टर दिखा रहे विपक्षी सांसदों को फटकार लगाते हुए कहा कि सड़क जैसा व्यवहार आप सदन में नहीं कर सकते। माननीय हो, माननीय बने रहो। आपको यहां जनता की आवाज उठाने, उसकी पीड़ा, चिंताओं के बारे में विमर्श करने के लिए भेजा गया है, आप ये सब मत करिए।

इसके बाद ओम बिड़ला ने सदन को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। जिस अंदाज में ओम बिड़ला ने विपक्ष को डांटा-फटकारा, यह अनोखा नहीं है। वे पहले भी सदन के भीतर मर्यादित आचरण बनाए रखने की नसीहत दे चुके हैं। ये और बात है कि उनकी नसीहत केवल विपक्ष के लिए रहती है। सत्ता पक्ष के लोगों पर वे ऐसी सख्ती नहीं दिखाते। अन्यथा किसी सांसद को धर्म के नाम पर अपशब्द कहना या संसद में खड़े होकर चुनावी भाषण देना या किसी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना, ये सारे कारनामे जो भाजपा ने किए हैं, वे नहीं हो पाते।

बहरहाल, विपक्ष भी अब जानता है कि सरकार सदन को चलने नहीं देना चाहती, क्योंकि उसे फिर कई ऐसे सवालों का सामना करना पड़ेगा, जिनके जवाब उसके पास नहीं है। सरकार केवल एक ही सूरत में सदन को चलाएगी, जब विपक्ष चुपचाप बैठ कर उसका एकालाप सुने। जो हाल इस वक्त के पत्रकारों का हो गया है, जिन्हें इस बात से भी आपत्ति नहीं होती कि प्रधानमंत्री मीडिया से संवाद करेंगे ऐसा क्यों कहा जाता है, जबकि श्री मोदी अपने से काफी दूर पत्रकारों को खड़ा कर अपना बयान सुनाकर चले जाते हैं। पत्रकार सामने रहें और देश का नेता बोले तो लोकतंत्र के बने रहने का भरम बना रहता है। वर्ना जो कुछ श्री मोदी हर सत्र की शुरुआत में आकर कहते हैं, वह प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के जरिए भी मीडिया संस्थानों तक पहुंचाया जा सकता है।

लोकतंत्र का भरम बनाए रखने में लोकसभा अध्यक्ष भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने विपक्ष को याद दिलाया है कि जनता ने आपको किसलिए संसद में चुन कर भेजा है। हालांकि जो नियम विपक्ष पर लागू होता है, वह सत्ता पक्ष पर भी लागू होता है। जनता के सवालों को सदन में अगर सरकार उठाने दे तो फिर यह गतिरोध बनेगा ही नहीं। विपक्ष के लोगों को अपने स्थान से उठकर सामने आने और नारेबाजी करने पर मजबूर ही इसलिए होना पड़ता है कि उनकी बातों को सरकार सुन नहीं रही है। सरकार ने यह तय कर लिया कि प्रधानमंत्री जब विदेश से लौटेंगे तब ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम मुद्दे पर जवाब देंगे।

लेकिन प्रधानमंत्री तो संसद शुरु होने के तीसरे दिन विदेश रवाना हुए हैं, जब जीएसटी लागू करने के लिए या वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करने के लिए आधी रात तक संसद चलाई जा सकती है, तो फिर देश की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े इतने गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए इंतजार क्यों करवाया जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है।

ऑपरेशन सिंदूर पर बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। पत्रकारों से चर्चा में राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ श्री मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, दूसरी तरफ वे विजय की बात भी करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्धविराम के दावे भी रुक नहीं रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने 25वीं बार यह दावा किया है कि व्यापार की धमकी देकर उन्होंने भारत और पाक के बीच युद्ध रुकवाया है। तीन महीनों में 25 बार एक ही बात का दावा करने की इस रफ्तार को देखें तो जल्द ही ट्रंप इस दावे का शतक बना लेंगे। क्या तब जाकर प्रधानमंत्री इस पर अपना पक्ष सामने रखेंगे और कहेंगे कि मैं कृष्ण की तरह शिशुपाल की सौ गलतियां पूरा होने का इंतजार कर रहा था।

बहरहाल, नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर यह हिम्मत न दिखा पाएं कि वे अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति के बयान पर कोई पलटवार करें, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते तो उन्हें इस बेहूदे दावे का जवाब देने में कोई देर नहीं करनी चाहिए। इस देश की दुनिया में अलग साख है और प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को इसकी गरिमा का अहसास होना चाहिए। यह समझ से परे है कि श्री मोदी सत्ता के 11वें साल में भी क्यों इस गरिमा से वंचित हैं। वे अमेरिका की तरफ से किए जा रहे इस अपमान पर एक बार सख्ती से जवाब देकर तो देखें, उन्हें खुद समझ आएगा कि भारत का प्रधानमंत्री होने के मायने क्या हैं।

लेकिन नरेन्द्र मोदी ने न विदेश में भारत की साख को बनाए रखा है, न वे देश में लोकतंत्र पर हो रहे प्रहार पर फिक्र कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के साथ-साथ बिहार में हो रहे मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ भी संसद में आवाज उठानी पड़ रही है। बुधवार को विपक्ष के सांसदों ने फिर से इसे लेकर प्रदर्शन किया और कई ने तो बाकायदा काले कपड़े भी पहने।

विपक्ष चाहता है कि सरकार इस मुद्दे पर भी चर्चा करे क्योंकि यह सीधे-सीधे मताधिकार पर चोट करने की प्रक्रिया है। जब वोट देने का अधिकार ही लोगों से छिन जाएगा, तब लोकतंत्र कहां तक और कब तक बचा रह पाएगा, यह एक गंभीर सवाल है।

क्रोनोलॉजी की भाषा में कहें तो लोग वोट नहीं दे पाएंगे, अपनी पसंद से जनप्रतिनिधि नहीं चुन पाएंगे, जिसकी सत्ता होगी, उसके लोग सदन में पहुंचेंगे और फिर उन्हीं लोगों की सुविधा के लिए कानून बनाएंगे, जिनसे सरकार को फायदा होता है और सरकार जिनको फायदा पहुंचाती है। इसमें लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की बुनियादी सुविधाएं, संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकार सब खत्म हो जाएंगे।

यानी मामला केवल एक राज्य में हो रही एसआईआर का नहीं है, इसके पीछे बड़ा खेल है जिसे उजागर करने में विपक्ष लगा है। लेकिन ओम बिड़ला समझा रहे हैं कि विपक्ष सड़क की तरह आचरण न करे। यानी भाजपा चाहती है कि उसके राज में सड़कें भी सूनी रहे और संसद भी।

दुनिया की लाखों जिन्दगियां में जहर घोलता अकेलापन

ललित गर्ग

'हर छठा व्यक्ति अकेला है'-यह निष्कर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ताज़ा रिपोर्ट का है, जिसने पूरी दुनिया को चिन्ता में डाला है एवं सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम कैसी समाज-संरचना कर रहे हैं, जो इंसान को अकेला बना रही है। निश्चित ही बढ़ता अकेलापन कोई साधारण सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि एक ऐसा वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है, जो व्यक्तियों, समाजों, और व्यावसायिक संस्थानों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है।

दुनिया के करोड़ों लोग टूटे रिश्तों व संवादहीनता की स्थितियों में नितांत खामोशी का जीवन जी रहे हैं। गौर करे तो इंसान के भीतर की ये खामोशी लाखों जिंदगियां में महामारी के रूप में जहर घोल रही है। विडंबना यह है कि इस संकट का सबसे ज्यादा शिकार युवा हो रहे हैं। वृद्ध तो पहले से ही सामाजिक एवं पारिवारिक विसंगतियों में उपेक्षित है। निश्चय ही जीवन की विसंगतियां एवं विषमताएं बढ़ी हैं। कई तरह की चुनौतियां सामने हैं। पीढ़ियों के बीच का अंतराल विज्ञान व तकनीक के विश्तार के साथ तेज हुआ है।

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की लगभग 16 प्रतिशत आबादी आज किसी न किसी रूप में अकेलेपन, सामाजिक अलगाव या भावनात्मक दूरी का शिकार है। यह स्थिति केवल वृद्धजनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि युवाओं, कामकाजी पेशेवरों, और यहां तक कि बच्चों तक फैल चुकी है। डिजिटल युग में जहां सब कुछ 'कनेक्टेड' लगता है, वहीं इंसानी रिश्तों में एक अदृश्य दूरी, कृत्रिमता और आत्मीयता का अभाव देखने को मिल रहा है।

सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में हम जितने अधिक जुड़े हैं, उतने ही भावनात्मक रूप से अकेले हो गए हैं। व्यक्तिवादी सोच, सामाजिक दुष्प्रभाव एवं रिश्तों की बिखरती दीवारों में अकेलेपन का घातक प्रभाव सामाजिक ढांचे पर गहरे रूप में पड़ रहा है। पारिवारिक संबंधों में दरारें, विवाहों में असंतोष, और तलाक की बढ़ती दरें इसकी साफ़ निशानी हैं। युवा पीढ़ी में अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति और नशे की ओर झुकाव एक चिंताजनक ट्रेंड बन गया है। बुजुर्गों में अकेलेपन से उत्पन्न अल्ज़ाइमर, डिमेंशिया और अन्य मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं।

अकेलापन केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक विफलता का संकेत है। जब हम तकनीक, दौड़ और स्वार्थ में इतने उलझ जाते हैं कि किसी के पास "सुनने का समय" नहीं रहता, तब अकेलापन जन्म लेता है।

अब समय आ गया है कि हम फिर से रिश्तों, संवाद और करुणा की दुनिया की ओर लौटें। अन्यथा अकेलापन, उदासी और असंतुष्टि की भावनाएं कचोटती रहेगी। मानो खुद के होने का एहसास, कोई इच्छा ही ना बची हो। तब छोटी-छोटी चीजों में छिपी खूबसूरती नजर ही नहीं आती। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से लोग जिंदा हैं, पर जीवित होने के जादुई एहसास को कम ही छू पाते हैं।

सोच के भौतिकवादी एवं सुविधावादी होने से हमारी आकांक्षाओं का आसमान ऊंचा हुआ है। लेकिन यथार्थ से साम्य न बैठा पाने से कुंठा, हताशा व अवसाद का विश्तार हो रहा है। जिसके चलते निराशा हमें एकाकीपन या अकेले होने की ओर धकेल देती है। निश्चित ही सोशल मीडिया का क्रांतिकारी ढंग से विश्तार हो रहा है। लेकिन इसकी हकीकत आभासी है, कृत्रिम है, दिखावटी है।

हर कोई सोशल मीडिया मंचों पर हजारों मित्र होने का दावा करता है, लेकिन ये मित्र कितने संवेदनशील है? कितने करीब है? इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक ही है, यथार्थ के जीवन में व्यक्ति बिल्कुल अकेला एवं गुमशुम होता है। आभासी मित्रों का कृत्रिम संवाद हमारी जिंदगी के सवालों का समाधान नहीं दे सकता, अकेलापन दूर नहीं कर सकता। निश्चित रूप से कृत्रिम रिश्ते हमारे वाश्तविक रिश्तों के ताने-बाने को मजबूत नहीं कर सकते।

विडंबना यह है कि कृत्रिमताओं के चलते कहीं न कहीं हमारे शब्दों की प्रभावशीलता में भी कमी आई है। जिससे व्यक्ति लगातार एकाकी जीवन की ओर उन्मुख होना लगा है। हमारे संयुक्त परिवारों का बदलता स्वरूप एवं एकल परिवारों का बढ़ता प्रचलन भी इसके मूल में है। पहले घर के बड़े बुजुर्ग किसी झटके या दबाव को सहजता से झेल जाते थे।

सब मिल-जुलकर आर्थिक व सामाजिक संकटों का मुकाबला कर लेते थे। लेकिन अब बुजुर्ग एकाकीपन एवं अकेलापन से जूझ रहे है। केरल में इसी तरह के वृद्ध-संकट को महसूस करते हुए वहां की सरकार ने वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाया है, जो एक सूझबूझभरा कदम है। आज वृद्धों को अकेलापन, परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षा, दुर्व्यवहार, तिरस्कार, कटुक्तियां, घर से निकाले जाने का भय या एक छत की तलाश में इधर-उधर भटकने का गम हरदम सालता रहता।

वृद्ध समाज इतना कुंठित, अकेला एवं उपेक्षित क्यों है, एक अहम प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार अनेक स्वस्थ एवं आदर्श समाज-निर्माण की योजनाओं को आकार देने में जुटी है, उन्हें वृद्धों को अकेलेपन को लेकर भी चिन्तन करते हुए वृद्ध-कल्याण योजनाओं को लागू करना चाहिए, ताकि वृद्धों की प्रतिभा, कौशल एवं अनुभवों का नये भारत-सशक्त भारत के निर्माण में समुचित उपयोग हो सके एवं आजादी के अमृतकाल में अकेलापन एक त्रासदी न बन सके।

कामकाजी परिस्थितियों का लगातार जटिल होना एवं महंगी होती जीवनशैली ने अकेलापन के संकट को गहरा बनाया है। उन परिवारों में यह स्थिति और जटिल है, जहां पति-पत्नी दोनों कामकाजी हैं और बच्चे हॉस्टलों व बोर्डिंग स्कूल में रह रहे हैं।

व्यावसायिक क्षेत्रों में भी काम का बोझ इंसानों को अकेला बना रहा है। कार्यालयों और कार्यस्थलों पर भी अकेलापन एक गंभीर चुनौती बन रहा है। कर्मचारी भावनात्मक जुड़ाव की कमी के कारण कार्य में रुचि नहीं लेते। टीम वर्क, इनोवेशन और सहयोग पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। अकेलापन लंबे समय तक बना रहा तो यह बर्नआउट, कार्य से असंतोष और कर्मचारी त्यागपत्र जैसी स्थितियों को जन्म देता है। इससे उत्पादकता में भी गिरावट आती है।

मेकिन्से और डेलॉइट जैसी वैश्विक कंसल्टिंग फर्म्स की रिपोर्टें दर्शाती हैं कि अकेलापन कर्मचारियों की उत्पादकता को 15-20 प्रतिशत तक घटा सकता है, जिससे कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। अकेलेपन के इस संकट से निपटने के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक और संस्थागत श्तर पर सामूहिक प्रयास ज़रूरी हैं।

परिवार, मित्रों और सहयोगियों के साथ समय बिताना ही असली 'समृद्धि' है। कंपनियों और संस्थानों में कर्मचारियों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को समझने वाला नेतृत्व चाहिए। डिजिटल संवाद की जगह आमने-सामने संवाद, 'वर्क फ्रॉम होम' की जगह 'वर्क विद कम्युनिटी' को प्राथमिकता देनी होगी। ऑफिसों और समाज में काउंसलिंग, समूह चर्चा, मेडिटेशन, और योग को प्रोत्साहन दिया जाए। सरकारों को अकेलेपन को एक जनस्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता देनी चाहिए और सामाजिक समावेश के लिए ठोस कार्यक्रम चलाने चाहिए।

डब्ल्यूएचओ का वह आंकड़ा भी चौंकाता है कि अकेलापन हर साल तकरीबन आठ लाख लोगों की जीवन लीला समाप्त कर रहा है। जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति न केवल समाज व अपने कार्यालयी परिवेश से अलग-थलग हुआ है, बल्कि वह परिवार से भी कटा है। पिछले दिनों देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने कार्यालयों में काम के घंटे बढ़ाने का आग्रह किया था।

एक उद्यमी ने तो यहां तक कहा कि क्या जरूरी है कि घर में रहकर पत्नी का ही चेहरा देखा जाए। यह एक संवेदनहीन एवं बेहूदा प्रतिक्रिया थी। दरअसल, लोगों में यह आम धारणा बलवती हुई है कि जिसके पास पैसा है तो वह सबकुछ कर सकता है। जिसके चलते उसने आस-पड़ोस से लेकर कार्यस्थल पर सीमित पहुंच बनायी है। यही वजह है कि हमारे इर्द-गिर्द की भीड़ और ऑनलाइन जिंदगी के हजारों मित्रों के बावजूद व्यक्ति अकेलेपन को जीने के लिये अभिशप्त है। सही बात ये है कि लोग किसी के कष्ट और मन की पीड़ा के प्रति संवेदनशील व्यवहार नहीं करते। हर तरफ कृत्रिमताओं का बोलबाला है। हमारे मिलने-जुलने वाले त्योहार भी अब दिखावे व कृत्रिम सौगातों की भेंट चढ़ गए हैं। हमें उन कारकों पर मंथन करना होगा, जिनके चलते व्यक्ति निजी

जल संकट : टिकाऊ प्रबंधन की अनिवार्यता

डॉ. शैलेश शुक्ला

विश्व बैंक (2025): विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट (अप्रैल 2025) में कहा गया है कि भारत, जो विश्व की 18% आबादी का घर है, के पास केवल 4% जल संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे यह विश्व के सबसे अधिक जल-तनावग्रश्त देशों में से एक है। जलवायु परिवर्तन और अनियमित मानसून ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। विश्व बैंक के अनुसार, वैश्विक श्तर पर लगभग 2.2 अरब लोग सुरक्षित पेयजल की पहुंच से वंचित हैं और 4.2 अरब लोगों को स्वच्छता सुविधाओं का अभाव है।

भारत में, नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि 2030 तक देश के 40% से अधिक हिस्से में गंभीर जल संकट हो सकता है। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहर पहले ही डे ज़ीरो की स्थिति का सामना कर चुके हैं, जहां जल स्रोत पूरी तरह सूख गए। यह आंकड़ा और भी भयावह है : भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1951 में 5,177 घन मीटर से घटकर 2025 में केवल 1,341 घन मीटर रह गई है।

यह स्थिति न केवल चिंताजनक है, बल्कि तत्काल कार्रवाई की मांग करती है। जल संकट अब केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकट का रूप ले चुका है। इस संपादकीय में, हम जल संकट के कारणों, प्रभावों और टिकाऊ जल प्रबंधन की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे, साथ ही भारत के संदर्भ में व्यावहारिक समाधानों का प्रश्ताव देंगे।

जल संकट के पीछे कई परस्पर जुड़े कारक हैं। सबसे पहले, जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण ने जल की मांग को अभूतपूर्व श्तर तक बढ़ा दिया है। भारत की जनसंख्या 1.4 अरब को पार कर चुकी है और 2030 तक 50% से अधिक लोग शहरों में रहने लगेंगे। शहरी क्षेत्रों में पानी की खपत ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक है, क्योंकि औद्योगीकरण, घरेलू उपयोग और जीवनशैली में बदलाव ने जल की मांग को बढ़ाया है।

दूसरा, जलवायु परिवर्तन ने जल चक्र को बाधित किया है। अनियमित मानसून, सूखा और बाढ़ की बढ़ती घटनाएं जल संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित कर रही हैं। उदाहरण के लिए, 2023 में भारत के कई हिस्सों में मानसून की बारिश औसत से 10-15% कम रही, जिसने जलाशयों और भूजल श्तर को और कम कर दिया। तीसरा, जल संसाधनों का अति-दोहन एक प्रमुख समस्या है। भारत में 80% से अधिक पेयजल और सिंचाई भूजल पर निर्भर है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार, देश के 17 राज्यों में भूजल श्तर अति-दोहन की श्रेणी में है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य, जो भारत के खाद्यान्न उत्पादन का केंद्र हैं, सबसे अधिक प्रभावित हैं।

चौथा, जल प्रदूषण ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। गंगा, यमुना और अन्य प्रमुख नदियां औद्योगिक कचरे, सीवेज और कृषि रसायनों से प्रदूषित हो चुकी हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 70% सतही जल प्रदूषित है, जिससे पेयजल की कमी और बढ़ रही है।

अंत में, नीतिगत और प्रशासनिक कमियां भी जिम्मेदार हैं। जल प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव, विभिन्न विभागों में समन्वय की कमी और अवैध जल उपयोग को रोकने में नाकामी ने संकट को गहरा किया है।

जल संकट के प्रभाव : जल संकट के प्रभाव बहुआयामी हैं। सबसे पहले, यह स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालता है। दूषित पानी के सेवन से डायरिया, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष 4 लाख से अधिक लोग जलजनित बीमारियों के कारण मरते हैं। दूसरा, जल संकट कृषि और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। भारत में 60% से अधिक कृषि सिंचाई पर निर्भर है और भूजल की कमी ने फसल उत्पादन को कम किया है। 2019 में, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में सूखे के कारण लाखों किसान प्रभावित हुए, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई।

तीसरा, जल संकट सामाजिक असमानता को बढ़ाता है। गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को स्वच्छ पानी की सबसे अधिक कमी झेलनी पड़ती है। महिलाएं और बच्चियां, जो अक्सर पानी लाने की जिम्मेदारी संभालती हैं, को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनकी शिक्षा और आजीविका पर असर पड़ता है। चौथा, जल की कमी औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। जल-गहन उद्योग जैसे कपड़ा, चमड़ा और बिजली उत्पादन पानी की कमी के कारण उत्पादन में कटौती कर रहे हैं। यह रोजगार और जीडीपी पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

टिकाऊ जल प्रबंधन की आवश्यकता : जल संकट से निपटने के लिए टिकाऊ जल प्रबंधन अपरिहार्य है। टिकाऊ जल प्रबंधन का अर्थ है जल संसाधनों का ऐसा उपयोग जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे, साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करे। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं : -

1. जल संरक्षण और पुनर्जनन : जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना आवश्यक है। भारत में, जहां औसतन 1,170 मिमी वार्षिक वर्षा होती है, वर्षा जल संचयन से भूजल श्तर को पुनर्जनन किया जा सकता है। तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्यों में वर्षा जल संचयन की सफल कहानियां प्रेरणादायक हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान के अलवर जिले में तारुण भारत संगठन ने पारंपरिक जोहड़ों के पुनरुद्धार से भूजल श्तर को 6-8 मीटर तक बढ़ाया है।

2. भूजल प्रबंधन : भूजल के अति-दोहन को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने होंगे। भूजल पुनर्भरण के लिए कृत्रिम रिचार्ज संरचनाएं, जैसे चेक डैम और तालाब, बनाए जाने चाहिए। साथ ही, किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी जल-कुशल तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

3. नदियों और जलाशयों का संरक्षण : नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए औद्योगिक कचरे और सीवेज के उपचार को अनिवार्य करना होगा। नमामि गंगे जैसे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। साथ ही, जलाशयों के अवसादन को रोकने के लिए वनीकरण और मृदा संरक्षण पर ध्यान देना होगा।

4. जल उपयोग में दक्षता : शहरी क्षेत्रों में जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए स्मार्ट मीटरिंग और लीकेज नियंत्रण आवश्यक है। बेंगलुरु जैसे शहरों में 40% से अधिक पानी पाइपलाइन लीकेज के कारण बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा, घरेलू श्तर पर जल-बचत उपकरणों, जैसे कम-प्रवाह वाले शावर और शौचालय, को बढ़ावा देना होगा।

5. नीतिगत सुधार : जल प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय जल नीति की आवश्यकता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करे। जल को एक सामुदायिक संसाधन के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, न कि निजी संपत्ति के रूप में। साथ ही, जल उपयोग के लिए मूल्य निर्धारण नीति लागू की जानी चाहिए, जो अति-उपयोग को हतोत्साहित करे।

6. सामुदायिक भागीदारी : जल प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। पंचायतों और स्थानीय निकायों को जल संरक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, सामुदायिक प्रयासों से हजारों चेक डैम बनाए गए, जिसने भूजल श्तर को सुधारा।

भारत में टिकाऊ जल प्रबंधन के उदाहरण

भारत में कई सफल उदाहरण हैं, जो टिकाऊ जल प्रबंधन की संभावनाओं को दर्शाते हैं। मेघालय के चेरापूंजी में, जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, सामुदायिक श्तर पर बांस-आधारित ड्रिप सिंचाई प्रणाली ने जल उपयोग को अनुकूलित किया है। आंध्र प्रदेश में, नीरू-चेट्टू कार्यक्रम ने जलाशयों और नहरों की मरम्मत के साथ-साथ वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है।

सरकारी श्तर पर किए गए विभिन्न प्रयास : भारत सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो नीति आयोग की 2018 की सिफारिशों से प्रेरित हैं : 1. जल शक्ति मंत्रालय (2019): जल प्रबंधन से संबंधित कार्यों को एकीकृत करने के लिए स्थापित किया गया। 2. अटल भूजल योजना (एबीवाई): भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए, विशेष रूप से जल-तनावग्रश्त क्षेत्रों में। 3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई): जल उपयोग की दक्षता और सिंचाई कवरेज बढ़ाने के लिए

निष्कर्षत : यह कहा जा सकता है कि जल संकट एक वैश्विक चुनौती है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए, जहां जल संसाधन सीमित हैं और मांग बढ़ रही है, यह एक आपातकालीन स्थिति है। टिकाऊ जल प्रबंधन केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। सरकार, समुदाय और व्यक्तियों को मिलकर इस संकट से निपटना होगा।

वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, प्रदूषण नियंत्रण और नीतिगत सुधार जैसे कदमों के माध्यम से हम न केवल जल संकट को कम कर सकते हैं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जो भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करे। यह समय है कि हम जल को एक अनमोल संसाधन के रूप में महत्व दें और इसके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएं।

चुनाव आयोग बनाम अदालत

चुनाव आयोग ने सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के संदर्भ में आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड 'वैध दशतावेज' नहीं हैं, लिहाजा उन्हें मान्यता नहीं दी जा सकती। बिहार में पुनरीक्षण का करीब 96 फीसदी काम पूरा हो चुका है।

चुनाव आयोग ने सर्वोच्च अदालत के आग्रह को नकार दिया है, लिहाजा अब न्यायिक पीठ का फैसला अथवा उसकी प्रतिक्रिया क्या रहती है, यह 28 जुलाई को सुनवाई के दौरान सामने आ सकता है। सर्वोच्च अदालत या तो न्यायिक आदेश देती है अथवा निर्देश देती है, जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए।

अब अदालत और आयोग दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी परस्पर मर्यादाएं हैं, लिहाजा अहम सवाल है कि क्या आयोग बनाम अदालत की स्थिति बन गई है? क्या शीर्ष अदालत भविष्य के मतदाता-सूची पुनरीक्षण के मद्देनजर आधार, वोटर और राशन कार्ड को वैध दशतावेज मानने को चुनाव आयोग को बाध्य कर सकती है? चुनाव आयोग ने यह भी दावा किया है कि मतदाता की नागरिकता का पता लगाना भी उसका संवैधानिक अधिकार है।

बेशक यह मुद्दा भी सर्वोच्च अदालत के सामने उठेगा, क्योंकि न्यायिक पीठ कहती रही है कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है।

वह गृह मंत्रालय का संवैधानिक जनादेश है। लिहाजा मतदाता-सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में, बिहार में ही, जिन 52 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटने की संभावना आयोग ने जताई है, क्या उनकी नागरिकता भी सवालिया हो जाएगी? यह तय करने वाला चुनाव आयोग कौन होता है? आयोग ने अभी तक जो डाटा इकट्ठा किया है, उसके मद्देनजर आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति में रेखांकित किया है कि बिहार की मतदाता सूचियों में करीब 18 लाख मृतकों के नाम दर्ज हैं, 26 लाख ऐसे नाम हैं, जो किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और वहां के मतदाता हैं, 7 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम दो-दो स्थानों पर हैं। इस तरह 52 लाख से अधिक नाम मतदाता-सूची से काटे जा सकते हैं।

बेशक ऐसे मतदाता 1 अगश्त से 1 सितंबर के दौरान अपील कर सकते हैं। क्या नागरिकता से जुड़े ऐसे मामले सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंच सकते हैं? बिहार में चुनाव आयोग के पुनरीक्षण-अभियान का जबरदश्त राजनीतिक विरोध किया जा रहा है। यहां तक कि विधानसभा में मेज-कुर्सियां उछाली गईं।

मार्शल (सुरक्षाकर्मी) और विपक्षी विधायक आपस में भिड़ गए, धक्कामुक्की, हाथापाई तक की नौबत आ गई। संसद परिसर में भी विपक्षी गठबंधन के सांसदों ने बैनर, पोस्टर, तख्तियां लेकर संसद भवन के 'मकर द्वार' पर विरोध-प्रदर्शन किया। संसद के भीतर विपक्षी सांसद अध्यक्ष के आसन तक 'वेल' में लामबंद हुए। नारेबाजी का शोर इतना था कि सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी। दोनों सदनों की कार्यवाही दोनों दिन नहीं चल सकी।

बेशक चुनाव आयोग के अभियान से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है अथवा नहीं, अलबत्ता लोकतंत्र लगातार 'लहूलुहान' जरूर हो रहा है। अब सर्वोच्च अदालत को एक निश्चित फैसला सुना कर देश के लोकतंत्र को बचाना है। अब तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बयानबाजी शुरू कर दी है कि आयोग बंगाल में ऐसे 40 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काट सकता है। संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 में चुनाव आयोग को पुनरीक्षण के संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। आयोग मतदाता-सूचियों में संशोधन कर सकता है। नाम काटे जा सकते हैं, तो नए मतदाताओं के नाम जोड़े भी जाते हैं। चूंकि आजकल बांग्लादेशी घुसपैठियों, म्यांमार की तरफ से रोहिंग्या मुसलमानों की चर्चा खूब है।

सरकारें अवैध घुसपैठियों को उनके देश वापस भेज रही है। यदि आधार, राशन, वोटर कार्ड जैसे सरकारी दशतावेज नकली, फर्जी बनाए जा रहे हैं, तो यह देश पर कलंक है। ऐसे कार्डधारकों की छंटनी होनी ही चाहिए।

भारत कोई धर्मशाला नहीं है। ऐसे माहौल में सर्वोच्च अदालत का दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है कि वह ऐसी छंटनी को वैधता प्रदान करे।

राहत में सियासत नहीं

राहत में सियासत की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिमाचली वजूद के प्रश्न अब तारों की छांव में नहीं, सिर्फ राजनीति के गलियारों में ही साबित होने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लगता है कि सराज, करसोग व नाचन के जख्मों की अनदेखी हो रही है।

जाहिर है जख्मों के जरिए न तो नमक हलाली खोजी जानी चाहिए और न ही इन्हें राजनीति के तराजू में तोला जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों की बुनियाद में भले ही उनकी विधानसभा के आंसू समाहित हैं, लेकिन यह वक्त साझी विरासत की किश्तियों का है। बाढ़ कोई खिलौना नहीं और न ही आपदा किसी वैमनस्य की गवाही हो सकती है।

यह विडंबना है कि आपदा के बावजूद जयराम बनाम जगत सिंह नेगी होने लगा। वजूद में आपदा लिए हम हिमाचल के प्रति लापरवाह तो कहे जाएंगे। आपदा आई कैसे और जाएगी कैसे, इस प्रश्न की पूर्णता में पूरा हिमाचल जोखिम से भरा है। आपदा में राहत के संदेश और सरकार के आदेशों से इतर भी समाज ने अपने हाथ बढ़ाए हैं। यही वजह है कि प्रशासन को कहना पड़ा कि अब मदद की पहुंच में किस-किस वश्तु की जरूरत है। मदद का कारवां सिर्फ मदद नहीं, यह राहत का आश्वासन है जिसे सामूहिकता से पूरा करना होगा, लेकिन विडंबना यह कि अब बयानों की चरागाह में भटकने लगा हिमाचल।

बाढग़्रश्त इलाकों में सत्ता और विपक्ष के अलावा पूरे हिमाचल के सरोकार अगर पहुंचे हैं, तो प्रभावित लोग गवाह हैं कि तिनके को तिनके का सहारा क्या होगा।

बेशक हिमाचल को अपने सीमित संसाधनों से अधिकतम व्यय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में करना होगा, लेकिन यहां राष्ट्र और हिमाचल के बीच फासलों का भी जिक्र होगा।

जिक्र होगा केंद्र की भूमिका का, उन अर्जियों का संदर्भ होगा जो दो साल पहले की दर्द को समेटे दिल्ली की ठोकरों में अपनी संवेदना का जिक्र कर रही थीं। राजनीति अगर सराज बनाम शिमला है, तो शिमला बनाम दिल्ली भी है।

हमारी पैरवी राष्ट्रीय आपदा के मानदंडों से है या आपदा के बीच सियासत को घसीटने की है। ईमानदारी से होना तो यह चाहिए कि पूरा हिमाचल केंद्र से अपने हिस्से की राहत मांगे। दिल्ली के दिल में हिमाचल के सात सांसदों का दिल एक साथ धडक़े, तो एकमुश्त किश्त तमाम बाढग़्रश्त इलाकों के राहत शिविर तक पहुंच जाएगी। बेशक हिमाचल में विकास के साथ जुड़ रहा विनाश काफी हद तक राजनीतिक या राजनीतिक प्राथमिकताओं की वजह से भी है।

हमारे विकास का मॉडल क्यों फेल हो रहा है, इसको लेकर भी तो थोड़ी सी राजनीति हो जाए। क्यों आज तक हिमाचल के नेता टीसीपी कानून की हड्डियां तोड़ते रहे।

अतिक्रमणकारी लोगों को प्रकृति से छेड़छाड़ करने की मोहलत देते रहे। जल, जंगल और जमीन को लेकर हमने कौनसी नीतियां बनाईं। राजनीति का चरित्र और हर सत्तारूढ़ दल का आचरण एक ही जैसा साबित हुआ।

साबित हुआ कि जिसकी चली या जो सत्ता का प्रभावशाली चेहरा था, उसने प्रगति के नाम पर कंक्रीट के जंगल में ऐसे विकास को उगा दिया, जो आज विनाश का सियापा कर रहा है। हम पहाड़ को अनुशासित होने के बजाय राजनीतिक प्राथमिकताओं की चरागाह बना रहे हैं।

ऐसी हजारों सरकारी इमारतें हैं, जिन्होंने विध्वंस का काम किया है। सारे राजनेता और जनप्रतिनिधि सोचें कि उनके हलके में कितनी जेसीबी मशीनें, कितने क्रशर और जमीन की खरीद-फरोख्त के सौदागर बढ़ गए।

हम जरूरतों के हिमाचल नहीं, हम छीना-झपटी के हिमाचल हैं। ऐसे में क्या आपदा राहत में भी छीना-झपटी होगी। क्या हमारे रहम में भी ईमानदारी नहीं। अगर हिमाचल की जनता किसी न किसी रूप में चंदा इकट्ठा करके राहत की सांसें बटोर सकती है, तो राज्य के सारे नेक राश्ते खुलने चाहिएं।

आपदा में लांछनों की आपदा अगर आमंत्रित कर ली, तो हम एक राज्य नहीं, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ या राजनेताओं के टीले ही बन जाएंगे। ये गलत परंपरा होगी, कहीं तो हम सियासत से हटकर इस दुख-दर्द में जीने और भविष्य संरक्षण का ईमानदार एहसास बनें।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती आशा शर्मा द्वारा 707 मंदाकिनी टावर सेक्टर -4, वैशाली गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) भारत से प्रकाशित एवं एन।सी।आर। प्रिंटर्स, 15/19 साइट-4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया जनपद गाजियाबाद से मुद्रित। **संपादक** : संजय शर्मा
फोन: 9899683800 वेबसाइट : www lncrtoday lin ई-मेल: todayncr@gmail।com >> ncrtoday@hotmail।com **RNI**-UPHIN/2009/30721

संक्षिप्त समाचार

पंडा दक्षिणा विवाद में पुलिस की कार्रवाई, चौकी प्रभारी समेत 24 लाइन हाजिर, आरक्षी निलंबित

मिर्जापुर, एजेंसी। विंध्याचल में दक्षिणा को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की तो कैंची से हमला पाया गया। मामले में उस स्थान पर ड्यूटी पर तैनात आरक्षी को निलंबित किया गया है। वहीं धाम चौकी प्रभारी समेत 24 को लाइन हाजिर किया गया।

बुधवार को विंध्याचल थाना क्षेत्र में पंडों के बीच दक्षिणा की बात को लेकर विवाद हुआ। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना में सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर पाया गया कि आरोपियों द्वारा घटना में धारदार हथियार के रूप में कैंची से हमला कर घायल कर दिया गया था।

पुलिस द्वारा विवेचना में जान से मारने का प्रयास एवं कानून व्यवस्था भंग करने की धाराओं की बढ़ोत्तरी किया गया है। घटना में प्रयुक्त कैंची को बरामद किया गया। वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा लापरवाही बरती गई। उन सभी 24 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। जिसमें चौकी प्रभारी धाम राजकुमार पांडेय भी शामिल हैं। घटनास्थल के निकट ड्यूटी पर मौजूद आरक्षी कांताराम को निलंबित कर दिया गया है।

केंद्रीय विद्यालय की अस्थायी कक्षाएं जीजीआईसी में शुरू

जौनपुर , एजेंसी। केंद्रीय विद्यालय पयागपुर की जीजीआइसी परिसर में चलने वाली अस्थाई कक्षाओं का बुधवार को राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव ने शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 का शुभारंभ किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने नवीन छात्रों को शिक्षण किट बांटी और कक्षाओं में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राज्य मंत्री जी ने कहा कि जनपद के लिए यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। आज केंद्रीय विद्यालय के शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ हुआ है। इसके लिए उन्होंने छात्रों और अभिभावकों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी और कहा कि निश्चित रूप से जनपद शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में रहा है। उन्होंने कहा कि उनके अनवरत प्रयास से विद्यालय के सत्र शुरू हो जाने से छात्रों को पठन पाठन में सुविधा होगी और उन्हें बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। उन्होंने नए छात्रों को शिक्षण किट का वितरण किया गया और कक्षों में व्यवस्थाओं को देखा। जिलाधिकारी डा. दिनेश चंद्र ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है जनपद में केन्द्रीय विद्यालय का सत्र प्रारंभ हुआ। मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जनपद के विकास को एक नई ऊंचाईपर ले जाया जाएगा। धन्यवाद ज्ञापन उप प्राचार्य एके सिंह ने किया। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट इन्द्र नंदन सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी डा गोरखनाथ पटेल सहित आदि उपस्थित रहे।

म्योर मिल की जमीन पर बनेंगे मंडलीय कार्यालय, मिल के अंदर हटीं मशीनें दुकानें हो चुकीं नीलामी

कानपुर , एजेंसी। कानपुर में सिविल लाइंस स्थित म्योर मिल की जमीन पर मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त कार्यालय समेत अन्य विभागों के मंडलीय कार्यालय बनेंगे। मिल की करीब डेढ़ लाख वर्ग मीटर नजूल संपत्ति का एडीएम वित्त, एसडीएम सदर और तहसीलदार सदर ने सर्वे कर लिया है। टीम ने मिल के स्वामित्व वाली जमीन को पहले सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने का प्रस्ताव तैयार किया है। माह के अंत तक प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा। सहमति मिलते ही कार्यालय निर्माण का प्रस्ताव भेजा जाएगा। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में सरकारी विभागों के मंडलीय कार्यालय संचालित हैं। कई विभागों के पास खुद की जमीन नहीं है। कई कलक्ट्रेट या किराये की इमारतों में संचालित हैं। इस समस्या के मद्देनजर जिला प्रशासन एक ही छत के नीचे मंडलीय कार्यालयों को बनाने के लिए लंबे समय से जमीन तलाश रहा था। बीते वर्ष सरकार की तरफ से नजूल की संपत्तियों पर सरकारी कार्यालय स्थापित करने की योजना तैयारी की गई थी। इस पर जिले के अफसरों ने नजूल की खाली संपत्तियों को खोजना शुरू किया।

नजूल विभाग से जमीन के सारे रिकॉर्ड देखे गए हैं- इसके बाद म्योर मिल की जमीन को चिह्नित किया। यह मिल कई वर्षों से बंद पड़ी है।

गोवंश दुर्दशा प्रकरण : अब एक और चुनौती...

डॉक्टर और कर्मचारियों का काम से इनकार, भूख से तड़प रहे गोवंश

मेरठ , एजेंसी। मेरठ के परतापुर स्थित कान्हा उपवन गोशाला चलाने में नगर निगम के सामने एक और चुनौती बन गई है। गोवंशों के इलाज करने वाले डॉक्टरों और गोशाला में कार्यरत कर्मचारियों ने कामकाज करने से मना कर दिया। निगम अफसरों ने इस पर पत्राचार भी शुरू कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि निगम ने तीन-चार महीने से वेतन तक नहीं दिया। गोवंशों की संख्या ज्यादा है और कर्मचारी बहुत कम है। नए कर्मचारियों को ढूंढने में नगर निगम के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि वहां पर कार्यदाई संस्था द्वारा ही कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। गोशाला में 2549 गोवंशों की देखरेख करने के लिए निगम की लिखापढ़ी में 54 कर्मचारियों तैनात हैं और वहां स्थायी एक भी डॉक्टर नहीं है। गोवंशों की दुर्दशा की पोल खुलने पर अब निगम की व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। गोशाला में तैनात महिला और पुरुषों ने काम करने से मना कर दिया हैं। उनका कहना है कि गोवंशों की संख्या ज्यादा होने के चलते गोशाला में काम बहुत हैं और 15 से ज्यादा रोजाना कर्मचारी नदारद रहते हैं।

बुधवार को चार महिला गोशाला नहीं पहुंची और अपने साथी कर्मचारियों से कहा कि अब वह काम नहीं करेंगी। इससे भी बुरा हाल गोवंशों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का है। निगम का दावा कि पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रियंका शर्मा की तैनाती है।

डॉ. प्रियंका का कहना है कि मेरा गोशाला से कोई लेनादेना नहीं है, मेरी पोस्टिंग पशु चिकित्सालय परतापुर में है। जहां से मैं 27 हजार पशुओं का इलाज करती हूं। कभी-कभी गोशाला से फोन आता है, तो मैं उपचार के लिए वहां पर चली जाती थी। गोशाला में कभी प्रभारी मंत्री और अधिकारी निरीक्षण करते थे, तब मुझे डॉ. हरपाल सिंह फोन करके बुला लेते थे।

गोशाला का कायाकल्प करने में उतरा नगर निगम

भूख के मरे गोवंशों के मामले में फजीहत होने के बाद नगर निगम अब गोशाला के कायाकल्प में जुटा है। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार की निगरानी में नए सिरे से गोशाला का विस्तार कर खामियों में सुधार किया जा रहा है।

15000 वर्ग मीटर में जगह चिह्नित कर उसको कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। अभी सात टीन-शेड है, जिसको बढ़ाकर आठ कराया जा रहा है। नए कर्मचारियों की तैनाती पर भी काम करने का दावा गया।

प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने गोशाला के निरीक्षण के बाद गैर जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करने और गोशाला की स्थिति में सुधार करने के निर्देश दिए थे। गोवंशों के रहने के लिए टीन-शेड डालकर नई यूनिट बनाने के लिए कहा था। हाल में बने गोशाला के वरिष्ठ प्रभारी अपर नगर आयुक्त पंकज सिंह कामकाज कराने में लग गए हैं।

सीसीटीवी, सिक्योरिटी गार्ड और पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती करने का दावा किया गया है। गोशाला की सफाई के लिए मिनी सीवर जेटिंग मशीन को लगाया गया है। गोशाला के बाहर गांव के श्मशान के पास गोबर और मलमूत्र को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है।

गोशाला में भ्रष्टाचार की जांच में आएगी कई जिम्मेदारों पर आंच

गोशाला में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की जांच की आंच कई जिम्मेदारों पर आएगी। पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. हरपाल सिंह व केयर टेकर भारत कुमार के अलावा कई लोगों के नाम पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आए हैं। इनके खिलाफ सुबूत जुटाए जा रहे हैं। बताया गया है कि शासन ने मेरठ पुलिस-प्रशासन के अफसरों से विभागीय जांच रिपोर्ट मांगी है। इस प्रकरण में जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की शासन की मंशा है।

गोवंशों की दुर्दशा के बाद प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी रहे डॉ. हरपाल सिंह के जेल जाने के बाद भी भाजपा नेता और पार्षदों में आक्रोश कम नहीं हो रहा है। पार्षदों द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर निगम के अफसरों पर भद्दे कमेंट कराने का सिलसिला जारी है। डॉ. हरपाल के अलावा गोशाला में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था कराने में अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ भी भाजपा नेता और पार्षद ने सोशल मीडिया पर मुहिम चला रखी है। जिस पर पुलिस की नजर है। सिविल लाइन थाने और परतापुर थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना पुलिस ने शुरू कर दी है।

एसएसपी डॉ. विपिन ताडा का कहना है कि इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। डॉ. हरपाल के पास से कुछ दस्तावेज मिले हैं, इसकी जांच करने में पुलिस जुट गई है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को पुलिस रिमांड पर भी लेगी। पैसे कौन-कौन लेते थे, इसकी भी जांच कराएंगे। नामजद निगम के लिपिक विकास शर्मा की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है।

प्रभारी मंत्री ने गोशाला का निरीक्षण किया, इसके बाद प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. हरपाल सिंह को हटाया गया। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव से जानकारी ली, इसके बाद मेरठ के प्रशासन में खलबली मची। सोमवार को परतापुर में दो कंपनी और सिविल लाइन थाने में डॉ. हरपाल पर सरकारी संपत्ति का गबन, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। मंगलवार को उन्हें कोर्ट ने पेश किया, जहां से उनको न्यायिक हिरासत में लेकर 14 दिन के लिए जेल भेजा।

डॉ. हरपाल सिंह के ऑफिस की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज मांगी है। गोशाला में चारे के नियमित बिल कौन सी फर्म से आते थे। लाठी-डंडों की सप्लाई के बिल देने वाली फर्म, नामजद दोनों कंपनियों का रिकॉर्ड, भूसा, चोकर, हरा चारा और अन्य सामान के बिल, भुगतान कैसे हुआ। डॉ. हरपाल के अलावा गोशाला की जिम्मेदारी किस-किसकी थी, इसको लेकर भी पुलिस निगम के अधिकारियों से पूछताछ करेगी।

मिर्जापुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हैंडपंप में टक्कर मारते हुए घर में घुसी, एक की मौत

मिर्जापुर , एजेंसी। मिर्जापुर जिले के जमुई-चुनार मार्ग पर जमुई ओवरब्रिज के समीप एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर हैंडपंप में टक्कर मारते हुए मार्ग के किनारे बने एक घर में घुस गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक महिला सहित दो अन्य घायल हो गए। जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। स्कॉर्पियो चालक के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के पुत्र यश की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। बृहस्पतिवार की सुबह तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जमुई की तरफ से चुनार जा रही थी। जमुई ओवरब्रिज के समीप वाहन अनियंत्रित होकर हैंडपंप में टक्कर मारते हुए बाएं पटरी पर बने अरुण विश्वकर्मा के मकान में घुस गई। वाहन की चपेट में आने से चुनार के टम्मलपट्टी निवासी मंगल जायसवाल (40) पुत्र स्व. गोपाल जायसवाल की मौत हो गई।

वहीं सरस्वती (32) तथा राजू प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत को देखते हुए राजू को ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। वाहन चला रहा अभय यादव मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तो वहीं घायल को अस्पताल भिजवाया। वाहन को कब्जे में ले लिया। वाहन चालक की गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। दो घंटे तक चुनार-जमुई मार्ग जाम रहा। मौके पर पहुंचे एसडीएम चुनार राजेश वर्मा और सीओ चुनार मंजरी राव के समझाने पर लोग माने और जाम समाप्त हुआ। चालक के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मृतक को दो पुत्र और एक पुत्री है।

आपदा प्राधिकरण की बैठक

✷एनसीआर टुडे. गाजियाबाद✷

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA के निर्देशानुसार तथा उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UPSDMA) के दिशा-निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व / सचिव, जिला आपदा प्राधिकरण श्री सौरभ भट्ट की अध्यक्षता में आईआरएस सदस्यों के साथ डीडीएमए गाजियाबाद की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जनपद के पाँच चिन्हित स्थलों पर मॉक ड्रिल आयोजित करने पर विश्तृत चर्चा हुई, जो 01 अगश्त 2025 को की जायेगी, जिसके लिए निर्धारित स्थल हैं — तहसील मोदीनगर का सरकारी कार्यालय, इंग्राह्म स्कूल राजनगर, जिला संयुक्त चिकित्सालय संजय नगर, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम डिपो लोनी तथा वीवीआईपी रेजीडेन्स।

इस अवसर पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राजस्व विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में आपदा के समय समन्वय, तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु रणनीतियों पर चर्चा की गई।

घरों पर चोरों का धावा, लाखों के जेवरात और नकदी चोरी

✷एनसीआर टुडे. नोएडा✷

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में रहने 3 लोगों के घरों पर चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपए कीमत के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए हैं। वहीं नोएडा के थाना सेक्टर-63 में रहने वाले एक शख्स के घर से चोरों ने कीमती मोबाइल फोन चोरी कर लिया है। चार थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं से घर बंद कर नौकरी पर जाने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। पीड़ितों की शिकायत पर संबंधित थाना पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

थाना सूरजपुर के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि कुंदन सिंह नामक शख्स ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह तिलपता गांव में रहता है। पीड़ित के अनुसार उसकी गैर मौजूदगी में अज्ञात बदमाशों ने उसके घर से सोने की चेन, सोने के लॉकेट, सोने की अंगूठी, सोने का ढोलना, तीन पायल, दो जोड़ी बिछिया, कान की बाली, कान के टॉप्स, नाक की बाली तथा 80 हजार रुपए नकद चोरी कर लिया है।

थाना सेक्टर-63 के प्रभारी निरीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि सौरभ पाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह चोटपुर कॉलोनी में रहता है। उन्होंने बताया कि पीड़ित के अनुसार अज्ञात बदमाशों में उनके घर से उसका कीमती मोबाइल फोन चोरी कर लिया है। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर घटना की रिपोर्ट दर्ज पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

थाना बादलपुर के प्रभारी निरीक्षक अमित भड़ाना ने बताया कि विशाल कुमार सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह आमका रोड ग्राम धूममानिकपुर स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहता है। पीड़ित के अनुसार अज्ञात बदमाशों ने उसके घर से एक लैपटॉप, सोने के लॉकेट, सोने का ढोलना, 30 हजार रुपए नकद और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया है।

इसके अलावा थाना बिसरख के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि विशाल कटियार नामक शख्स ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह सेक्टर-2 में रहता है। पीड़ित के अनुसार वह अपना घर बंद करके फरीदाबाद स्थित अपने पैतृक गांव गया था। जब वह वापस आया तो उन्होंने देखा कि चोरों ने उसके घर का ताला तोड़कर घर में रखे हुए जेवरात, नकदी, दश्तावेज और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया है।

चार थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं से घर बंद कर नौकरी पर जाने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं पीड़ितों की शिकायत पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

किस काम का आयोग, परीक्षा की तारीख तक नहीं कर सका घोषित, भटक रहे लाखों अभ्यर्थी

प्रयागराज, एजेंसी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को दो साल हो गए हैं। आयोग की अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय को कार्यभार ग्रहण किए 10 माह से अधिक हो चुका है, जबकि आयोग के 12 सदस्यों की नियुक्ति तो अध्यक्ष से पहले मार्च-2019 में ही कर दी गई थी। आयोग के गठन की तैयारी वर्ष 2022 में ही शुरू कर दी गई थी। गठन के नाम पर अशासकीय विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी के 4163 पदों एवं अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी। आयोग का गठन जिस उद्देश्य से किया गया, वह अब तक पूरा ही नहीं हुआ। टीजीटी-पीजीटी परीक्षाएं तीन बार स्थगित की जा चुकी हैं। इसकी वजह से फॉर्म भरने वाले 13.19 लाख अभ्यर्थी परेशान हैं। हद तो तब हो गई जब आयोग ने बिना कोई नोटिस जारी किए टीजीटी परीक्षा स्थगित कर दी, जिसके लिए 8.69 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। टीजीटी-पीजीटी परीक्षा कब होगी, इस पर आयोग ने अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। वहीं, 16 और 17 अप्रैल 2025 को हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम भी अब तक घोषित नहीं किया गया है। परीक्षा में गड़बड़ी आने के बाद शासन ने चार सदस्यीय टीम का गठन किया था, जिसकी निगरानी में परीक्षा परिणाम तैयार किया जाना है। आयोग नई भर्ती शुरू करने में भी अब तक विफल रहा है। बुधवार को छात्र प्रतिनिधिमंडल की बैठक में प्रतियोगी छात्रों ने ये सभी मुद्दे उठाए और कहा कि आयोग जब अपने गठन के उद्देश्य को ही पूरा नहीं कर पा रहा है तो वह किस काम का है।

मांग की गई कि आयोग टीजीटी-पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथि व असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का परिणाम शीघ्र जारी करे और नई भर्ती भी शुरू करे। बैठक में शीतला प्रसाद ओझा, सचिन शुक्ला, अनीता तिवारी और महेंद्र पाल आदि मौजूद रहे।

मेट्रो की गलत डाली सीवर लाइन, सात वार्डों में भर गया सीवर का पानी, अब मरम्मत में भी कर रहा हीलाहवाली

कानपुर, एजेंसी। कानपुर में मेट्रो की लापरवाही की वजह से गोविंदनगर सहित सात वार्डों की सड़कों और घरों में सीवर का पानी भर रहा है। बरसात के बाद से यह समस्या काफी बढ़ गई है। करीब साढ़े तीन लाख लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। यूपीएमआरसी मरम्मत कराने के बजाय बार-बार कोरे आश्वासन दे रहा है। टूटी सीवर लाइन में मात्र एक डीवाटरिंग पंप लगाया गया है जो नाकाफी है। इसे देखते हुए जलकल विभाग ने बुधवार को दूसरा पंप लगाया। जलकल विभाग के यूपीएमआरसी के जीएम ने मरम्मत कराने के लिए मेट्रो को फिर पत्र लिखा है।

यूपीएमआरसी ने जूही हमीरपुर रोड पर एलिवेटेड मेट्रो निर्माण के दौरान गहरी सीवर लाइन तोड़ने के बाद मानकों के विपरीत वैकल्पिक सीवर लाइन डाली। जूही गढ़ा में गहरी सीवर लाइन से जोड़ने के लिए चैंबर बनाया पर उसका पाइप ठीक से नहीं जोड़ा। इस वजह से दो महीने पहले चैंबर के आसपास की सड़क धंस गई थी। कई बार धरना-प्रदर्शन के बावजूद मेट्रो ने आश्वासन ही दिया। निकासी न होने से सीवर लाइन में गंदा पानी इकट्ठा होने लगा। हाल ही में हुई बारिश के बाद सीवर लाइन का पानी पहले सड़कों पर आया और फिर घरों तक पहुंच गया।

इन वार्डों में भर रहा गंदा पानी: जलकल विभाग जोन-3 की अधिशासी अभियंता नबीला खान ने बताया कि मेट्रो की लापरवाही की वजह से सब्जी मंडी किदवईनगर और जूही कला वार्ड में सीवर भराव हो रहा है। जोन-5 के अधिशासी अभियंता रामेंद्र पांडेय ने बताया कि जूही गढ़ा में गहरी सीवर लाइन का चैंबर टूटने से जूही, गोविंदनगर उत्तरी, गोविंदनगर दक्षिणी, गोविंदनगर कच्ची बस्ती और निरालानगर वार्ड में गंदा पानी भर रहा है। गोविंदनगर 13 ब्लॉक, नंदलाल चौराहे के आसपास सहित कई जगह बारिश होने पर कई-कई दिन तक पानी भर रहा है। इस समस्या से गुस्साए भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित, सरोज चड्ढा, शालू कनौजिया, अमित जायसवाल आदि ने आंदोलन की चेतावनी दी है।

राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव का दावा- 18 महीने में छह करोड़ श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन

अयोध्या , एजेंसी। मणिराम दास की छावनी में संचालित श्रीराम कथा महोत्सव में पहुंचे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसी साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कथा श्रोताओं को मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक की पूरी कहानी बताई। चंपत राय के अनुसार 22 जनवरी 2024 को हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 18 माह में छह करोड़ से अधिक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं।

चंपत राय ने बताया कि मंदिर वास्तुकला एवं तकनीक का संगम है। मंदिर एक हजार साल तक खड़ा रहे, इसके लिए कई कंपनियों की मदद ली गई है। मंदिर में एक प्रतिशत भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर की नींव पत्थरों की चट्टान पर निर्मित है। जमीन में वर्षा की नमी पत्थरों को नुकसान न पहुंचा पाए इसलिए नमी सोखने वाले ग्रेनाइट पत्थर का नींव में इस्तेमाल किया गया है।

मंदिर के दरवाजे सदियों तक चमकते रहें इसके लिए सागौन की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। रामलला की मूर्ति कैसी हो इसको लेकर देश के नामी मूर्तिकारों के साथ मंथन किया गया। तीन मूर्तिकारों ने मूर्ति बनाई थी, जिसमें से एक मूर्ति का चयन हुआ, जो आज राम मंदिर के भूतल पर स्थापित है। प्रथम तल पर राम दरबार की भी स्थापना हो चुकी है।

परकोटा में छह मंदिर, सप्त मंडपम में सात मंदिर बनाए गए हैं। राम जन्मभूमि परिसर भविष्य में सामाजिक समरसता का भी बड़ा केंद्र बनकर सामने आएगा। कहा कि इस समय एक घंटे में सुविधापूर्वक रामलला के दर्शन हो रहे हैं। कथा क्रम में उत्तम स्वामी ने प्रवचन की सरिता प्रवाहित की।

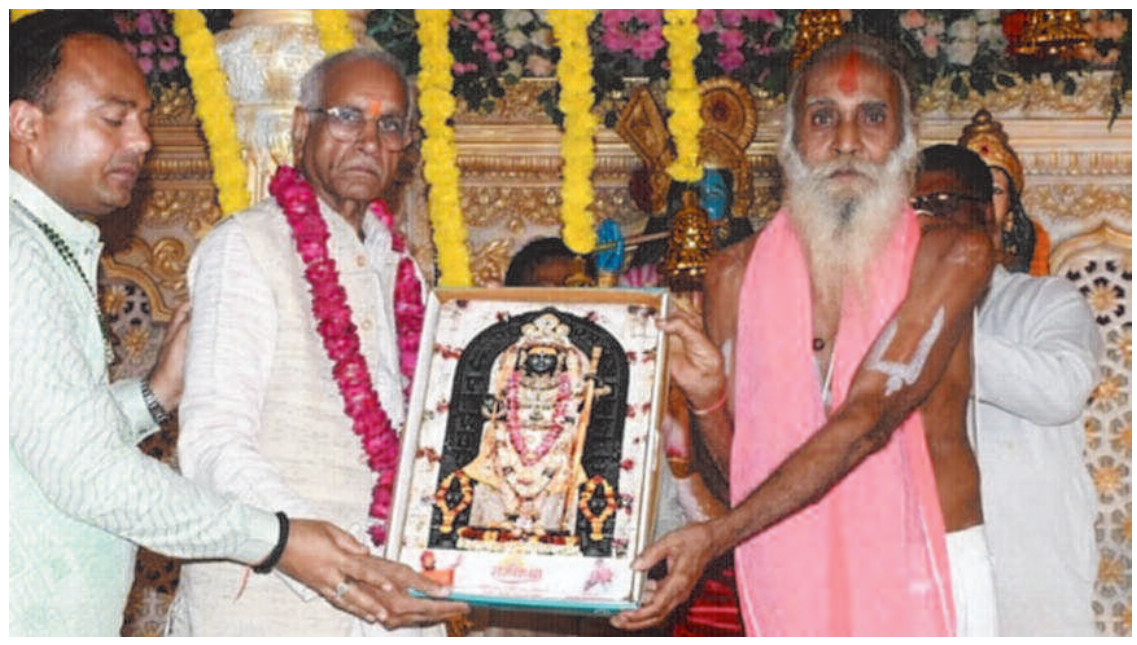

पूर्व सीएम कल्याण सिंह की समाधि पर बनेगा स्मारक स्थल

अलीगढ़ , एजेंसी। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रहे स्व. कल्याण सिंह 'बाबूजी' की स्मृति में बुलंदशहर जिले के नरौरा में भव्य समाधि एवं स्मारक स्थल बनने जा रहा है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम और प्रमुख सचिव सिंचाई टी. वेंकटेश के साथ लखनऊ में हुई बैठक में अंतिम रूप देते हुए इस योजना को पास किया गया। इसका नक्शा भी पास हो गया है। इससे कल्याण सिंह के समर्थकों में बेहद खुशी है।

इस बैठक में शामिल रहे राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि नरौरा स्थित बाबूजी का समाधि स्थल केवल एक स्मारक भर नहीं रहेगा, बल्कि यह एक राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और जनसेवा की भावना के जीवंत केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यहां आने वाले लोग बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ उनके विचारों, संघर्षों और सिद्धांतों से भी प्रेरणा लेंगे। यह स्मारक न केवल अतीत की गौरवगाथा के रूप में पहचाना जाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सेवा, संकल्प और संस्कार का आदर्श केंद्र भी बनेगा।

बाबूजी कुशल प्रशासक और राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता थे। लोक कल्याण की भावना ने उन्हें जनमानस में बाबूजी की संज्ञा दिलाई। संदीप सिंह ने कहा कि अब वे उसी पवित्र धरती पर स्थायी स्मृति के रूप में स्थापित होंगे, जहां वे पंचतत्व में विलीन होकर इतिहास का अंग बने।

भारत-पाक मैच पर भी आया अपडेट

सितंबर में खेला जाएगा 2025 एशिया कप, वेन्यू का हो गया खुलासा!

नई दिल्ली, एजेंसी। एशिया कप 2025 को लेकर आखिरकार अच्छी खबर सामने आई है. अब तक संशय की स्थिति बनी हुई थी कि इस साल एशिया कप का आयोजन होगा भी या नहीं. अब मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार एशिया कप 2025 की मेजबानी दुबई, अबू धाबी करने वाला है. यह टूर्नामेंट 5 सितंबर-21 सितंबर तक खेला जाएगा. एशिया कप में भारतीय टीम के खेलने पर भी कुछ स्पष्ट नहीं था, लेकिन ताजा अपडेट अनुसार इस टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान समेत कुल 8 टीम भाग लेने वाली हैं.

अभी तक बीसीसीबाई, एसीसी और आईसीसी ने इस संबंध में कोई आधिकारिक स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया अनुसार भारतीय टीम भी इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली है. टूर्नामेंट में भाग लेने वाले देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान, यूएई और हॉन्ग कॉन्ग होंगे.

एशिया कप का आयोजन आखिरी बार 2023 में ओडीआई फॉर्मेट में खेला गया था, जिसके फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से रौंदा था. अभी तक यह साफ नहीं है कि एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच होगा या नहीं, क्योंकि अभी तक पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया गया है. बता दें कि फिलहाल इंग्लैंड में खेली जा रही वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में भी भारत बनाम पाकिस्तान मैच होने वाला था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में खेलने से इनकार कर दिया था.

ऐसे में आयोजकों को इंडिया चैंपियंस बनाम पाकिस्तान चैंपियंस मैच को रद्द करना पड़ा था. पिछले संस्करण से उलट एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. यह पहली बार होगा जब किसी एशिया कप टूर्नामेंट में कुल 8 टीम भाग ले रही होंगी. इस बार एशिया कप में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी टी20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं.

वैभव को पछाड़ आयुष म्हात्रे ने रचा इतिहास, इंग्लैंड के खिलाफ 206 रन ठोक कर बनाए कई रिकॉर्ड

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे ने इंग्लैंड के खिलाफ यूथ टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 206 रन जड़ डाले और एक नहीं बल्कि कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं. उन्होंने न केवल छक्कों के मामले में वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ा, बल्कि भारतीय अंडर-19 टेस्ट इतिहास में बतौर कप्तान सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं.

वैभव से 2 छक्के ज्यादा लगाकर बनाया नया रिकॉर्ड

जहां वैभव सूर्यवंशी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और छक्कों के लिए पहचाने जाते हैं, वहीं उनके ओपनिंग पार्टनर और कप्तान आयुष म्हात्रे अब उनसे 2 छक्के ज्यादा लगाकर आगे निकल चुके हैं. इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दो यूथ टेस्ट मैचों की सीरीज में आयुष ने कुल 9 गगनचुंबी छक्के लगाए, जबकि वैभव ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 छक्के लगाए थे.

सौरभ तिवारी का रिकॉर्ड भी टूटा

इससे पहले 2007-08 में सौरभ तिवारी ने यूथ टेस्ट सीरीज में 8 छक्के लगाए थे. इस बार आयुष ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और एक सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय अंडर-19 खिलाड़ी बन गए हैं. इनमें से 6 छक्के उन्होंने एक ही पारी में लगाए, जो अपने आप में एक दमदार प्रदर्शन रहा.

कप्तान ने ठोके 206 रन

दूसरे यूथ टेस्ट में आयुष ने पहली पारी में 80 रन, और दूसरी पारी में 126 रन की शानदार पारी खेली. कुल मिलाकर उन्होंने मैच में 206 रन बनाए और बतौर कप्तान अंडर-19 टेस्ट में 200+ रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड तन्मय श्रीवास्तव ने हासिल किया था, जिन्होंने 2006 में एक यूथ टेस्ट में 199 रनों की शानदार पारी खेली थी. रेड बॉल में वैभव से भी आगे निकले आयुष वैभव सूर्यवंशी की ताकत जहां व्हाइट बॉल क्रिकेट में मानी जाती है, वहीं आयुष म्हात्रे ने साबित कर दिया कि रेड बॉल क्रिकेट के राजा वो हैं. इंग्लैंड के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी न सिर्फ दमदार रही, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत संकेत भी दे गई.

भारतीय क्रिकेटर आवेश खान की हुई सफल सर्जरी, LSG फ्रेंचाइजी ने उठाया पूरा खर्चा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेटर आवेश खान की सफल सर्जरी हुई, जिसकी जानकारी लखनऊ सुपर जायंट्स ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी. वह इंडियन प्रीमियर लीग में इसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं, जिसके कप्तान ऋषभ पंत हैं. सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के अनुसार आवेश की सर्जरी और रिहैब का पूरा खर्चा लखनऊ फ्रेंचाइजी ही उठाएगी. तेज गेंदबाज आवेश खान को आईपीएल 2025 से पहले भी घुटने में चोट लगी थी, हालांकि वह इससे रिकवर हो गए थे और बीसीसीआई ने उन्हें टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत दी थी. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स के कई खिलाड़ी आईपीएल 2025 में चोट से जूझ रहे थे.

आवेश खान की घुटने की सर्जरी हुई

रिपोर्ट के अनुसार आवेश खान और मोहसिन खान की घुटने की सर्जरी मुंबई के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. दिनशॉ पारदीवाला द्वारा की गई. आवेश के दाएं पैर के घुटने की सर्जरी 17 जून को हुई. इसी रिपोर्ट में बताया गया कि आवेश खान, मोहसिन खान और मयंक यादव रणजी ट्रॉफी के पहले हाफ से बाहर हो सकते हैं, इन तीनों के टूर्नामेंट के सेकंड हाफ में खेलने की उम्मीद है. सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के अनुसार आवेश खान की सर्जरी का पूरा खर्चा लखनऊ सुपर जायंट्स ने उठाया. रिहैब का खर्चा भी टीम ही कर रही है. उम्मीद है कि वह रणजी ट्रॉफी के दूसरे हाफ में खेल सकते हैं.

दिव्या एफआईडीई विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची

जॉर्जिया (एजेंसी)। भारतीय ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया में चल रहे एफआईडीई विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। दिव्या इस टूर्नामेंट के इतिहास में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। यह जीत उनकी लगातार तीसरी ऐसी जीत है, जिसमें उन्होंने एक ग्रैंडमास्टर को मात दी।

इस जीत के साथ ही दिव्या ने अपना पहला ग्रैंडमास्टर नॉर्म हासिल किया और 2026 एफआईडीई महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की की। वहीं, कोनेरू हम्पी का फैसला आज टाई-ब्रेकर मैच (रैपिड/ब्लिट्ज) से होगा। चीनी खिलाड़ी टिंगजी लेई के खिलाफ दोनों गेम ड्रॉ रहा।

दिव्या ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को हराया

दिव्या ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन तान झोंग्यी को सेमीफाइनल मुकाबले में 1.5-0.5 के अंतर से हराया। 19 साल की दिव्या ने सफेद मोहरों से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया और 101 चाल में मात दी। दूसरे गेम में उन्हें सफेद मोहरों से खेलने का फायदा मिला। उन्होंने बीच के खेल में लगातार दबाव बनाया और तान झोंग्यी को गलतियां करने पर मजबूर कर दिया।

व्हाइट (दिव्या) क्लीन की अदला-बदली के साथ जीत की स्थिति में थी, लेकिन क्लीन को बोर्ड पर रखने से भी उनकी स्थिति बहुत मजबूत थी।इसके बाद झोंग्यी ने वापसी की और बढ़त ले ली। समय की कमी में झोंग्यी ने गलत चाल चली, जिसके बाद दिव्या दो प्यादों की बढ़त के साथ आगे हो गईं। आखिरी गेम में झोंग्यी के पास ड्रॉ के कई मौके थे, लेकिन वह इन्हें भुना नहीं सकीं।

पहला गेम रहा था ड्रॉ

पहले गेम में दिव्या ने काले मोहरों से खेला था। यह गेम ड्रॉ रहा था। दिव्या ने पहले गेम के शुरुआत में ही खेल को संतुलित करने की रणनीति अपनाई। झोंगयी ने 'क्वीन्स गैम्बिट डिक्लाइन्ड' ओपनिंग से खेल की शुरुआत की, जिसमें दिव्या ने लगातार मोहरे बदलते हुए संतुलन बनाए रखा। झोंगयी भी इस स्थिति से संतुष्ट दिखीं, जहां ब्लैक को थोड़ी सक्रियता मिली थी।

डीसी ओपन टेनिस:

फ्रिट्ज ने डीसी ओपन के तीसरे दौर में बनाई जगह, वीनस विलियम्स युगल में बाहर

वॉशिंगटन, एजेंसी। पहले दौर में बाई मिलने के बाद फ्रिट्ज़ अब तीसरे दौर में माटेओ अर्नाल्डी का सामना करेंगे, जिन्होंने 16वें नंबर के खिलाड़ी लोरेंजो सोनेगो को 7-5, 7-5 से हराया। शीर्ष वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज़ ने सीधे सेट में जीत दर्ज करके डीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में जगह बनाई लेकिन एक साल से भी अधिक समय बाद वापसी करने वाली वीनस विलियम्स को महिला युगल में हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले फ्रिट्ज ने अलेक्जेंडर वुकिक पर 6-3, 6-2 से जीत हासिल की। पहले दौर में बाई मिलने के बाद फ्रिट्ज़ अब तीसरे दौर में माटेओ अर्नाल्डी का सामना करेंगे, जिन्होंने 16वें नंबर के खिलाड़ी लोरेंजो सोनेगो को 7-5, 7-5 से हराया। महिला वर्ग में दूसरी वरीयता प्राप्त एम्मा नवारो को मारिया सकारी ने 7-5, 7-6 (1) से हरा दिया। इस बीच वीनस विलियम्स और उनकी जोड़ीदार हैली बैप्टिस्ट का युगल में अभियान दूसरे दौर में चैंपियन टाईब्रेकर में दूसरी वरीयता प्राप्त टेलर टाउनसेंड और झांग शुआई की जोड़ी से 6-4, 3-6, 10-6 से हार के साथ समाप्त हो गया।

China Open Badminton: चाइना ओपन में सात्विक-चिराग क्वार्टर फाइनल में, प्रणय को मिली हार

चांग्झू, एजेंसी। विश्व की पूर्व नंबर एक भारतीय जोड़ी ने अपने धैर्य का अच्छा नमूना पेश करते हुए एक कड़े मुकाबले में आठवीं वरीयता प्राप्त इंडोनेशियाई जोड़ी पर 21-19, 21-19 से जीत हासिल की। सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने गुरुवार को इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नांडो और बगास मौलाना को सीधे गेम में हराकर चाइना ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि, एचएस प्रणय 65 मिनट

तक चले पुरुष एकल के दूसरे दौर के मैच में चीनी ताइपे के छठे वरीय चोऊ तिएन चेन से 21-18, 15-21, 8-21 से हारकर बाहर हो गए। विश्व की पूर्व नंबर एक भारतीय जोड़ी ने अपने धैर्य का अच्छा नमूना पेश करते हुए एक कड़े मुकाबले में आठवीं वरीयता प्राप्त इंडोनेशियाई जोड़ी पर 21-19, 21-19 से जीत हासिल की। सात्विक और चिराग को जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि दोनों ही गेम में पलड़ा इधर से उधर झुकता रहा। पहले गेम में इंडोनेशियाई जोड़ी ने पहले 8-6 और बाद में 14-12 की मामूली बढ़त बना ली थी, लेकिन भारतीय जोड़ी ने 14-16 के स्कोर के बाद लगातार पांच अंक जीतकर 19-16 से बढ़त बना ली और फिर पहला गेम अपने नाम कर दिया। दूसरे गेम में भी यही स्थिति रही। एक समय लियो और बगास 14-10 की बढ़त बनाए हुए थे।

एशिया जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप

वेन्नाला कलागोटला और तन्वी शर्मा ने भारत को दिलाई शानदार शुरुआत

सोलो (इंडोनेशिया), एजेंसी। बैडमिंटन एशिया जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप 2025 में भारत ने शानदार शुरुआत की है। महिला एकल वर्ग में वेन्नला कालागोटला और तन्वी शर्मा ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर भारतीय अभियान को मजबूत बढ़त दिलाई। वेन्नला कालागोटला ने अलिसा कूलेशोवा को सिर्फ 15 मिनट में 21-6, 21-10 से शिकस्त दी। इसके बाद उन्होंने इंडोनेशिया की औबर्टा जर्लिना को 21-18, 21-16 से हराकर गुरुवार को होने वाले राउंड ऑफ-32 में जगह बना ली। दूसरी वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा ने यूएई की वैदेही कालिदासन को आसानी से 21-6, 21-6 से हराया, जबकि तन्वी रेड्डी ने चिओक इयान उंग को 21-9, 21-10 से पराजित किया।

सिर्फ एक गोल से इतिहास रच गई ये खिलाड़ी

इंग्लैंड और स्पेन में महिला यूरो कप 2025 की फाइनल जंग

नई दिल्ली, एजेंसी। महिला यूरो कप 2025 के ब्लॉकबस्टर मैच का इंतजार अब खत्म हो गया है। खिताबी भिड़ंत के लिए दो टीमें तय हो चुकी है। यूरो कप फाइनल मुकाबला रविवार, 27 जुलाई को स्विट्जरलैंड के बासेल में होगा। स्पेन और इंग्लैंड दोनों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। ऐसे में अब इन दोनों की टक्कर खिताबी भिड़ंत के लिए होगी। सेमीफाइनल में स्पेन की टीम ने रोमांचक अंदाज में जीत दर्ज की। जर्मनी के खिलाफ टीम ने एक मात्र गोल अतिरिक्त समय में किया।

स्पेन के लिए यह गोल ऐताना बोनमाटी ने किया जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बीमार होने के कारण कुछ दिन अस्पताल में भर्ती थी। वहीं इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में इटली को 2-1 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। बता दें कि लायनेसेस के नाम से मशहूर इंग्लैंड की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी शानदार डिफेंस और खतरनाक आक्रमण से विरोधियों की हालत खराब करके रखी है।

कप्तान लिया विलियमसन के नेतृत्व में अब टीम की कोशिश होगी कि वह लगातार दूसरे खिताब को अपने नाम करें। इंग्लैंड के लिए पूरे टूर्नामेंट में फॉरवर्ड बेथ मीड और एला टूने ने जीत के लिए अपना दम लगाया है। इसके अलावा गोलकीपर मैरी अर्प्स की चपलता से इंग्लैंड ने महत्वपूर्ण बचाव किए।

पहली बार यूरो कप के फाइनल में पहुंची है स्पेन

दूसरी ओर स्पेन ने जर्मनी को 1-0 से हराकर महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनाई है। स्पेन को ये जीत अतिरिक्त समय में किए गए गोल की मदद से मिली है। दोनों टीम निर्धारित समय में गोल नहीं कर पाई थी इसके बाद दो बार की बैलन डीओर विजेता बोनमाटी ने अतिरिक्त समय में 113वें मिनट में निर्णायक गोल किया। यूरो 2025 का फाइनल 2023 में खेले गए महिला विश्व कप के फाइनल की पुनरावृत्ति होगा। तब स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया था।

स्पेन की जर्मनी के खिलाफ यह पहली जीत थी। वह पहली बार यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा है। स्पेन ने पिछले दो साल में विश्व कप और नेशंस कप जीते हैं और अब उसकी निगाह खिताब की हैट्रिक पूरी करने पर होगी। यूरो 2025 के लिए बोनमाटी की तैयारियां उस समय गंभीर रूप से प्रभावित हो गई थी जब टूर्नामेंट से एक सप्ताह से भी कम समय पहले बार्सिलोना की मिडफील्डर को वायरल मैनिंजाइटिस के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था।